रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

3 JUN 1971

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 8, 1971/वैशाख 18, 1893
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 8, 1971/VAISAKHA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 1921.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission, in consultation with the Government of Gujarat, hereby nominates Shri L. R. Dalal, Chief Secretary to the Government of Gujarat, General Administration Department, as the Chief Electoral Officer for the State of Gujarat with effect from the 26th April, 1971 and until further orders *vice* Shri M. G Shah granted leave.

[No. 154/4/71.]

By Order,
ROSHAN LAL, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 1971

एस० ओ० 1921.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग गुजरात सरकार के

परामर्श से, श्री एम० जी० शाह की छुट्टी स्वीकार होने पर, श्री एल० आर० दलाल, मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, को 26 अप्रैल, 1971 से अगले आदेशों तक गुजरात राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है ।

[सं० 154/4/71]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव ।

ORDERS

New Delhi, the 19th March 1971

S.O. 1922.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vimal Kumar Pathak, Gram Jamul, Post Jamul Cement Works, Drug District (Madhya Pradesh) a contesting candidate for bye-election to the House of the People from Durg constituency, held on the 9th June, 1970 has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the Peopel Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vimal Kumar Pathak to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-HP/18/70(Bye).]

आदेश

नई दिल्ली 19 मार्च 1971

एस० ओ० 1922.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 9 जून, 1970 को हुए लोक सभा के निर्वाचन के लिए दुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विमल कुमार पाठक ग्राम जामुल पो० जामुल सीमेंट वर्क्स जिला दुर्ग (म० प्र०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विमल कुमार पाठक को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[म० प्र०-लो० स०/18/70 (उप)]

New Delhi, the 13th April 1971

S.O. 1923.—Whereas Dr. B. Puttakamaiah, Vijaya Clinic, Sira Town, Mysore State, who was a contesting candidate for election to the Mysore Legislative Assembly from 49-Sira Constituency, held in February, 1967 was disqualified by the Commission by its Order No. MY-LA/49/67, dated the 13th January, 1969 under section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for his failure to lodge the account of his election expenses in the manner required by the said Act and the Rules made thereunder;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Election Commission for the reasons recorded on the representation made by the said candidate Dr. B. Puttakamaiah, reduces the period of disqualification imposed on him to the period of disqualification already suffered by him and removes the disqualification for the unexpired period with immediate effect.

[No. MY-LA/49/67.]

By Order,
K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल 1971

एस० ओ० 1923.—यत: डा० बी० पुट्टकामैया, विजय क्लिनिक सीरा टाऊन मैसूर, जो विधान के लिए फरवरी, 1967 में हुए निर्वाचन में 49—सीरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन आयोग द्वारा उसके आदेश सं० मैसूर—वि० स०।49।67, तारीख 13 जनवरी, 1969 द्वारा उक्त अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण निरर्हित कर दिए गए थे ।

अत:, अब उक्त, अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त अभ्यर्थी डा० बी० पुट्टकामैया द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर अभिलिखित कारणों से उस अधिरोपित निरर्हता की कालावधि को घटाकर उतनी ही करता है जितनी वह वास्तव में सहन कर चुके हैं और उपरोक्त निरर्हता की अनवसित कालावधि को इसी समय से हटाता है ।

[संख्या मैसूर—वि० स०/49/67]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

New Delhi, the 31st March 1971

S.O. 1924.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Khem Karan, R/o village Musepur, Post Office Jalalpur, District Sitapur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for the bye-election held in 1969, to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 105-Sarojininagar Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Khem Karan, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/105/69/Bye(169).]

By Order,
A. N. SEN, Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1971

एस० ओ० 1924—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1969 को हुए उत्तर प्रदेश के लिए उप-निर्वाचन के लिए 105 सरोजनी नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव वाले उम्मीदवार श्री क्षेम करन, ग्राम मसेपुर पो० जलालपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री क्षेम करन को संसेद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०-प्र०-वि० स०/105/69/उप (169)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 7th April 1971

S.O. 1925.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, in sub-rule (2) of rule 11, for the word "pension", the following words shall be substituted, namely:—

"pension or special contribution to Provident Fund."

[No. E(D & A)67 RG 6-13.]

C. S. PARAMESWARAN, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1925.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1.(1) ये नियम रेल सेवक (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम 1968 में नियम 11 के उप-नियम (2) में "पेंशन" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"पेंशन या भविष्य निधि में विशेष अंशदान"

[सं० ई० (डी० एण्ड ए०) 67 आर जी 6–13]

सी० एस० परमेश्वरन्, सचिव ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 22nd April, 1971

S.O. 1926.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 49 to G. G. S. III in Gujarat State, pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying the Pipe Line from Well No. 49 to GGS III (Crude Line) width 20 Meters.

State: Gujarat District: Gujarat Taluka: Kadi

Village	S. No.	Hectare	Are	P. Are.
Ambavpura	119/5	0	7	20
,,	110	8	8	40

[No. 11/1/71-Lab. & Legis-I.]

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1926.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होती है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कुआं संख्या 49 से जी जी एस III तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख-भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा –9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कुआं संख्या 49 से जी जी एस III (फ्लो लाइन) चौड़ाई 20 मीटर

राज्य गुजरात जिला गुजरात तालुका काडी

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर इ	पी० ए आर इ
अम्बावपुरा] .	119/5	0	7	20
,,	119	0	8	40

[संख्या 11/1/71—लेबर एण्ड लेजिस 1]

S.O. 1927.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. K-141 to G. G. S. V in Gujarat State, pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from well No. K-141 to G.G.S. V

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	P. Are
Chatral	303	0	8	71
	331	0	3	90

1	2	3	4	5
	332	0	8	64
	324	0	4	03
	325	0	2	56
	323	0	13	72
	353	0	9	03
	Survey No			
Isand	683	0	10	15
	682	0	8	07

[No. 11/1/71-Lab. & Legis.-2.]

का०ग्रा० 1927—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह ग्रावश्यक है कि गजरात राज्य में कुग्रां संख्या केज्ञ 141 से जी० जी० एस० V तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

ग्रौर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध ग्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का ग्रधिकार ग्रर्जित करना ग्रावश्यक है ;

ग्रत:, ग्रब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के ग्रधिकार का ग्रर्जन) ग्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का ग्रधिकार ग्रर्जित करने का ग्रपना ग्राशय एतद् द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचेपाइपलाइन बिछाने के लिए ग्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग , निर्माण ग्रौर देख-भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बरोदा–9 को इस ग्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ग्रौर एसा ग्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तित: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

ग्रनुसूची

कुग्रां संख्या के –141 से जी जी एस V तक पाईप लाइन

राज्य गुजरात जिला महसाना तालुका कलोल

गांव .	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए ग्रार इ	पी० ए ग्रार इ
छतराल . .	303	0	8	71
	331	0	3	90
	332	0	8	64
	324	0	4	03
	325	0	2	56
	353	0	15	72
	353	0	9	03

1	2	3	4	6
	सर्वेक्षण संख्या			
इसंद	683	0	10	15
	682	0	8	07

[संख्या 11/1/71—लेबर एण्ड लेजिस–2]

S.O. 1928.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Collector line at Jn. point to Kalol Industries in Gujarat State, pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50) of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying the Line for Kalol Industries Gas Distribution Line

State : Gujarat Dist : Mehsana Taluka : Kalol

Village	S. No.	Hectare	Are	P. Are
Kalol	252/209/1	0	5	64
,,	205/209/1	0	3	60
,,	252/211	0	0	70
,,	252/210	0	7	22
,,	252/241	0	7	32
,,	252/242	0	9	80
,,	252/244	0	0	34
,,	252/243	0	5	52
,,	252/47	0	18	10
,,	252/2	0	2	52
,,	252/3	0	1	34
,,	363	0	1	70
,,	364/P	0	0	20
,,	362	0	0	40
,,	366	0	1	39
,,	448	0	2	01
,,	449	0	0	51
,,	446/	0	60	85
,,	381/P	0	2	36
,,	376	0	0	48
Arsodia	131	0	4	8
,,	129	0	8	40
,,	125/2	0	8	40
,,	122/P	0	0	72
,,	122	0	3	48
,,	121	0	8	52
Kalol Arsodia Cart Track		0	0	98

1		2	3	4	5
,,	. . . . .	108	0	20	52
,,	. . . . .	107/2	0	7	32
,,	. . . . .	107/1	0	14	16
		125/3	0	4	68
SAIJ	. . . . .	239/P	0	5	76
,,	. . . . .	239/P	0	7	20
,,	. . . . .	38/2	0	10	20
,,	. . . . .	237	0	10	60
,,	. Kalol Bhoyan	Cart Track	0	0	72
,,	. . . . .	221/P	0	17	88
,,	. . . . .	218	0	6	72
,,	. . . . .	217	0	6	60
,,	. . . . .	215/2	0	24	84
,,	. . . . .	210/P	0	14	40
,,	. . . . .	210/P	0	17	64
,,	. . . . .	168	0	3	00

[No. 11/1/71-Lab. & Legis.-3.]

M. V. S. PRASADA RAU, Under Secy.

का० आ० 1928— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलक्टर लाइन जंक्शन प्वांइट से कलोल उद्योगों तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है :

अतः, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कलोल उद्योग गैस वितरण लाइन के लिए लाइन बिछाने के लिये

राज्य गुजरात जिला महसाना तालुका कलोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	पी ए आर इ
कलोल	252/209/1	0	5	64
	205/209/1	0	3	60
	252/211	0	0	70
	252/210	0	7	22

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	पी ए आर ई
	252/241	0	7	32
	252/242	0	9	60
	252/244	0	0	84
	252/243	0	5	52
	252/247	0	18	10
	252/2	0	2	52
	252/3	0	1	84
	363	0	1	70
	364	0	0	20
	362	0	0	40
	368	0	1	39
	448	0	2	01
	449	0	0	51
	446/पी	0	0	85
	381/पी	0	2	36
	376	0	0	48
अरसोडिया	131	0	4	8
	129	0	8	40
	125/2	0	8	40
	122/पी	0	0	72
	122	0	3	48
	121	0	8	52
कलोल अरसोडिया कार्ट ट्रैक		0	0	96
	108	0	20	52
	107/2	0	7	52
	107/1	0	14	16
	125/3	0	4	68
	239/पी	0	5	76
	239/पी	0	7	20
	238/2	0	10	20
	237	0	10	68
		कलोल मोयान कार्ट ट्रैक		
		0	0	72
	221/पी	0	17	88
	218	0	6	72
	217	0	6	60

1	2	3	4	5
	215/2	0	24	84
	210/पी	0	14	40
	210/पी	0	17	64
	168	0	3	00

[सं० 11/1/71-लेबर एण्ड लेजिस-3]

म० वे० शिवप्रसाद राव, अवर सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTICE

New Delhi, the 29th April 1971

S.O. 1929.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said rules, by Shri T. Dulipsingh, Advocate 2nd floor Catholic Centre, Armenian Street, Post Box No. 121, Madras-1 for appointment as a Notary to practise in whole of India.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F.22/31/70-Judl.III.]

B. SHUKLA, Competent Authority.

गृह मंत्रालय

नोटिस

नई दिल्ली 29 अप्रैल 1971

एस०ओ० 1929.—इसके द्वारा लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरी रुल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकरण को श्री टी० दलीपसिंह अधिवक्ता, दूसरी मंजिल, कैथोलिक सन्टर, आरमेंनिअन स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स नं० 121 मद्रास-1 ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, सम्पूर्ण भारत में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रुप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दी जायें ।

[सं० 22/31/70-न्यायिक-III]

ब्रह्मानन्द शुक्ल,
सक्षम प्राधिकारी ।

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 1st May 1971

S.O. 1930.—The following draft of amendments to the Animal Casings Grading and Marking Rules, 1964 which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is published as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken into consideration on or after the 15th June, 1971.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Amendments

1. (1) These rules may be called the Animal Casings Grading and Marking (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause (b) of rule 2 of the Animal Casings Grading and Marking Rules, 1964 (hereinafter referred to as the said rules), after item (ii) but before the "Explanation", the following item shall be inserted, namely:—

"(iii) in the case of dry ready-to-wet casings of sheep and goats, measurement of the diameter of the casing after treatment with water for at least fifteen minutes".

3. In sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) in the case of dry ready-to-wet casings of sheep and goats, hanks, rings or cocoons may be made up of several pieces joined together with adhesive and other material which have been duly approved before hand by the Agricultural Marketing Adviser to the FGovernment of India".

4. In Schedule I to the said rules, under column 3 relating to "Special characteristics",—

(1) against the grade designation 'Grade' I, the existing entry shall be re-numbered as item (i) and after item (i) as so re-numbered, the following items shall be inserted, namely:—

"(ii) total fat streaks shall not exceed 40 per metre,

(iii) the middle of the seam shall be free from fat streaks, and

(iv) a streak of fat shall not exceed 3 cm. in length and 1 cm. in breadth";

(2) against the grade designation 'Grade II', in the existing entry, the words and figures "not exceeding 60 per metre" shall be inserted at the end;

(3) against the grade designation 'Grade III', in the existing entry, the words and figures "and/or having fat streaks in excess of 60 per metre" shall be inserted at the end.

[No. F. 13-6/70-C&M.]

K. RAJAN, Under Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 1 मई, 1971

एस०ओ० 1930.—पशु के सिंग श्रेणीकरण और चिन्ह नियम, 1964 के संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उत्पादन (श्रेणीकरण और चिन्हनन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा

की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर 15-6-71 को या उसके पश्चात् विचार किया जायगा ।

यदि उक्त प्रारुप की बाबत किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट तारीख से पहले कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होता है तो उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

संशोधनों का प्रारूप

1. (1) इन नियमों का नाम पशु-के सिंग श्रेणीकरण और चिह्न. संशोधन नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. पशु के सिंग श्रेणीकरण और चिह्न नियम, 1964 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (ख) की मद (ii) के पश्चात् किंतु स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"(iii)भेड़ों और बकरियों की सूखी, भिगोई जाने को तैयार, केसिंग की दशा में, जल में कम से कम पन्द्रह मिनिट तक सिझाने के पश्चात् केसिंग के व्यास का माप ।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (2) की मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(ग) भेडों और बकरियों की सूखी, भिगोई जाने को तैयार केसिंग की दशा में, अट्टियां बलय या कोकून को ऐसे कई टुकडों से बनाया जाएगा जो भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा पहले से ही सम्यक रुप से अनुमोदित आर्सेजक और अन्य पदार्थ के साथ जोडे गए होंगे ।

4. उक्त नियमों की अनुसूची I में "विशेष लक्षणों" से सम्बन्धित स्तम्भ 3 के नीचे-

(i) "श्रेणी 1" के श्रेणी अभिधान के सामने, विद्यमान प्रविष्टि मद (i) के रूप में पुनःसंख्यांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित मद (1) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात -

(ii) चर्बी की कुल रेखाए, प्रति मीटर 40 से अधिक नहीं होंगी ।

(iii) जोड़ का मध्य भाग चर्बी की रेखाओं से मुक्त होगा ।

(iv) चर्बी की रेखा लम्बाई में 3 सें० मी० और चौडाई में 1 सें० मी० से अधिक नहीं होगी ।

(2) "श्रेणी 2" के श्रेणी अभिधान के सामने , विद्यमान प्रविष्टि के अन्त में "जो प्रति मीटर 60 से अधिक न हो" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(3) "श्रेणी-3" के श्रेणी अभिधान के सामने , विद्यमान प्रविष्टि के अन्त में "और/या जिनमें चर्बी की रेखाएं प्रति मीटर 60 से अधिक हों" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[संख्या 13-6/71-सी० एण्ड एम०]

के० राजन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 30th April 1971

S.O. 1931.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-30/61-MI, dated the 26th July, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualification, Doctor of Medicine granted by the University of Oklahoma, U.S.A. shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Jessie Lee Cavener who possesses the said qualification is for the time being attached to the Wanless Hospital, Miraj Medical Centre, Post Miraj, M. H. Sangli District, Maharashtra for the purposes of teaching, research and charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. Jessie Lee Cavener is attached to the said Wanless Hospital, Miraj Medical Centre, Post Miraj, M. H. Sangli, District, Maharashtra whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. F.19-32/70-M.P.T.]

P. C. ARORA, Under Secy.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थय विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1971

का० आ० 1931.—यत: भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 26 जुलाई, 1962 की अधिसूचना संख्या 16-30/61-चि० 1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजन के लिए यूनिवर्सिटी आव आंक्लहोमा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रदत्त डाक्टर आफ मैडिसिन नामक चिकित्सा अर्हता मान्य अर्हता होगी ;

और यत: डा० जैस्सी ली कावेनर जिनके पास उक्त अर्हता है, शिक्षण, अनुसंधान और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए फिलहाल वैन्लैस हास्पिटल, मिराज, मैडिकल सैंटर, पोस्ट मिराज, एम० एच० सांगली, जिला महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं ,

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(i) इस आदेश के सरकारी राजपत्र म प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि; अथवा

(ii) उस अवधि को जब तक डा० जैस्सी ली कावेनर उक्त वैन्लेस अस्पताल, मिराज मेडिकल सैंटर, पोस्ट मिराज, एम० एच० सांगली, जिला महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर मैडिकल प्रक्टिस कर सकेंगे ।

[सं० 19-32/70-एम० पी० टी०]

पी० सी० अरोरा, अवर सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 24th April 1971

S.O. 1932.—Whereas the Central Government, being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), [being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3841, dated the 11th November, 1970] service in any oil-field, to be a public-utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 22nd November, 1970;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said service to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 22nd May, 1971.

[No. F. S. 11025/13/71-LR.I.]

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1971

का० आ० 1832.—यतः केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना [भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3841, तारीख 11 नवम्बर, 1970] द्वारा किसी तेल-क्षेत्र में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 नवम्बर, 1970 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ।

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढाया जाना अपेक्षित है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 मई, 1971 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस०-11025/13/71-एल० आर०

ORDER

New Delhi, the 30th April 1971

S.O. 1933.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the National Insurance Company Limited, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs National Insurance Company Limited, Calcutta, in making deductions from the wages of their workmen, who could not attend their duties on the 5th and 6th August, 1970 was justified? If not, to what relief are they entitled?"

[No. L.17011/2/71-LR.I.]

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 1971

का० आ० 1933.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नेशनल इंस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र की अपने उन कर्मकारों की जो की, अपने काम पर हाजिर न हो सकें, मजदूरी में से 5 और 6 अगस्त, 1970 को कटौतियां करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल० 17011/2/71-ए० आर० I]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th April 1971

S.O. 1934.—In the Schedule to the Order of the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. 3464, dated the 7th October, 1970, published in Part II Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 24th October, 1970, *for* the words "Hindu Bank Limited" *read* "Hind Bank Limited"

[No. 23/58/69/LRIII.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 1971

का० आ० 1934.—भारत के राजपत्र, तारीख 24 अक्टूबर, 1970 के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 3464, तारीख 7 अक्टूबर, 1970 की अनुसूची में "हिन्दू बैंक लिमिटेड" शब्दों के लिए "हिन्द बैंक लिमिटेड" पढ़िए :

[संख्या 23/58/69/एल० आर० 3]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 26th April 1971

S.O. 1935.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3261, dated the 8th September, 1970 the Central Government having regard to the location of the Central Workshop, Rajasthan Ground Water Board, Industrial Estate, Jodhpur, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said workshop from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 30th January, 1971 upto and inclusive of the 29th January, 1972.

[No. F. 601(78)/70-HI.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1971

का० आ० 1935.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3261 तारीख 8 सितम्बर, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय कर्मशाला, राजस्थान भू-जल बोर्ड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जोधपुर की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मशाला कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से 30 जनवरी, 1971 से 29 जनवरी, 1972 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं०फा० 601(78)/70-एच०आई०]

New Delhi, the 27th April 1971

S.O. 1936.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, (Department of Labour and Employment) No. S. O. 384 dated the 13th January, 1971 the Central Government having regard to the location of the factory, namely, Aluminium Industries, Ltd., Hyderabad in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of six months with effect from the 1st February, 1971 upto and inclusive of the 31st July, 1971.

[No. F. 601(27)/70-HI.]

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1971

का० आ० 1936.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 384 तारीख 13 जनवरी, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार ऐलुमिनियम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद, नामक कारखाने की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्र-

हणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से प्रथम फरवरी, 1971 से 31 जुलाई, 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० फा० 601(27)/70–एच०आई०]

S.O. 1937.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the Government Printing Press and Stationery Depot, Baroda in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said Depot from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year with effect from the 26th November, 1970 upto and inclusive of the 25th November, 1971.

[No. F. 602(52)70-HI.]

का० आ० 1937.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सरकारी मुद्रणालय और लेखन सामग्री डिपो, बड़ोदा की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त डिपो को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 26 नवम्बर, 1970 से 25 नवम्बर, 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० फा० 602(52)70/एच० आई०]

S. O. 1938.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Mysore in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter V A of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl No.	Name of district	Name of area	Name of the Factory
1	2	3	4
1	Bellary	Kudilgi	M. S. R. T. C. Depot, Kudilgi, Bellary District.
2	Kolar	Kolar	M. S. R. T. C. Kolar Depot, Kolar.
3	North Kanara . .	Agasur	The Gangavathi Co-operative Tile Factory Agasur, Ankola Taluk, North Kanara District.
4	South Kanara . . .	Surathkal	Government Ice and Cold Storage-cum-Freezing Plant Surathkal, South Kanara District.

[No. F. S.-38014(3)/71-HI]

का० आ० 1938.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की मैसूर राज्य में, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, में जिनमें

उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पूर्वतर हो, एतद्द्वारा छूट देती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बेल्लारी	कुडिलगी	एम० एस० आर० टी० सी० डिपो, कुडिलगी, बेल्लारी जिला ।
2	कोलार	कोलार	एम० एस० आर० टी० सी० कोलार डिपो, कोलार ।
3	उत्तर कनारा	आगासर	दि गंगावधी कोऑपरेटिव टाइल फैक्ट्री आगासर, अंकोला तालुक, उत्तर कनारा जिला ।
4	दक्षिण कनारा	सूरथकल	हरकारी बर्फ और शीतसंग्रहागार-एवं-हिमकारी संयंत्र, सूरथकल, दक्षिण कनारा जिला ।

[फाइल संख्या एस-38014(3)/71-एच०आई०]

New Delhi, the 29th April 1971

S.O. 1939.--Whereas Messrs Gannon Dunkerley and Company Limited, Chartered Bank Building, Fort, Bombay (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952);

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the Said Act, and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme and in pursuance of sub-section (3) of the said section 17, the Central Government hereby directs that,—

(a) the employer in relation to the said establishment shall pay within fifteen days of the close of the month to the Employees' Provident Fund, inspection charges at the rate of 0.09 per cent (zero point zero nine per cent) of the pay (basic wages, dearness allowance, retaining allowance, if any, and cash value of food concession admissible thereon);

for the time being payable to the employees of the said establishment who would have become members under the said Scheme but for this exemption;

(b) the said employer shall invest the provident fund contributions in accordance with the directions issued by the Central Government from time to time.

THE SCHEDULE

1. The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government may, from time to time, prescribe.
2. The employer shall furnish to each employee an Annual Statement of Account or Pass Book.
3. All expenses involved in the administration of the Fund including the maintenance of accounts, submission of accounts and returns, transfer of accumulations, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the Rules of the Fund as approved by the appropriate Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.
5. Where an employee who is already member of the Employees' Provident Fund (Statutory Fund) or the Provident Fund of another exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Fund of the establishment, and accept the past accumulations in respect of such employee and credit to his account.
6. The employer shall enhance the rate of provident fund contribution appropriately if the rate of provident fund contributions for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the Employees' Provident Funds Act, 1952 so that the benefits under the provident fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefit provided under the Employees' Provident Fund Act, 1952.
7. The establishment shall submit an audited balance sheet of its provident fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner within 3 months of the close of the year.
8. No amendment of the rules of the provident fund shall be made without the previous approval of the Central Provident Fund Commissioner. Where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Central Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

[No. 11/33/70-PF.II.]

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 1971

का० आ० 1939—यतः मेसर्स गेनन डन्करले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग फोर्ट बम्बई (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छूट देने के लिए आवेदन किया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय में अभिदाय की दरों की दावत उक्त स्थापन के भविष्य निधि नियम उसके कर्मचारियों के लिए उन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं, और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसविधाएँ भी पा रहे हैं जो कर्मचारियों के लिए कुल मिलकर उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल नहीं हैं, जो उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियोंकेसम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन दी जाती है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एतद्द्वारा छूट देती है और उक्त धारा 17 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि—

(क) उक्त स्थापन को सम्बद्ध नियोजक उक्त स्थापन के उन कर्मचारियों को, जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अधीन सदस्य हो गए होते, तत्समय देय वेतन के (आधारिक मजदूरी, मंहगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, और उस पर अनुज्ञेय खाद्य रियायत का नगद मूल्य) 0.09 (शून्य दशमलव शून्य नौ) प्रतिशत की दर से निरीक्षण-प्रभार मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि को देगा;

(ख) उक्त नियोजक भविष्य निधि अभिदायों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए निदेशों के अनुसार, विनिहित करेगा।

अनुसूची

1. नियोजक प्रादेशिक/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे विवरणियां भेजेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विहित करे।

2. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा-विवरण या पास बुक भेजेगा।

3. निधि के प्रशासन, जिसमें लेखाओं का बनाए रखना, लेखाओं और विवरणिओं का भेजा जाना, संचयों का अन्तरण, निरीक्षण-प्रभारों आदि का सन्दाय सम्मिलित है, में अन्तर्वलित सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जाएगा तब कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य-मुख्य बातों का अनुवाद भी प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी निधि) या छूट-प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित होता है तो नियोजक स्थापन को निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ही दर्ज करेगा और कर्मचारी की बाबत उसके पिछले संचयों को स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा।

6. यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए, जिसमें नियोजक का स्थापन आता है, भविष्य निधि के अभिदायों की दर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन बढ़ा दी जाए तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधाएं उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हो जाएं जिनकी व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन है।

7. स्थापन अपनी भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलन-पत्र हर वर्ष प्रादेशिक/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा।

8. भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो वहां प्रादेशिक/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व, कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

[संख्या 11/33/70-पी० एफ०-2]

S.O. 1940.—Whereas Messrs Nichimen Company Limited, 116, Stephen House, Calcutta (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the Said Act, and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act and under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar charactor;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme and in pursuance of sub-section (3) of the said section 17, the Central Government hereby directs that,—

(a) the employer in relation to the said establishment shall pay within fifteen days of the close of the month to the Employees' Provident Fund, inspection charges at the rate of 0.09 per cent (zero point zero nine per cent) of the pay (basic wages, dearness allowance, retaining allowance, if any, and cash value of food concession admissible thereon) for the time being payable to the employees of the said establishment who would have become members under the said Scheme but for this exemption;

(b) the said employer shall invest the provident fund contribution in accordance with the directions issued by the Central Government from time to time.

THE SCHEDULE

1. The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government may, from time to time, prescribe.

2. The employer shall furnish to each employee an Annual Statement of Account or Pass Book.

3. All expenses involved in the administration of the Fund including the maintenance of accounts, submission of accounts and returns, transfer of accumulations, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the Rules of the Fund as approved by the appropriate Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee who is already member of the Employees' Provident Fund (Statutory Fund) or the Provident Fund of another exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Fund of the establishment, and accept the past accumulations in respect of such employee and credit to his account.

6. The employer shall enhance the rate of provident fund contribution appropriately if the rate of provident fund contributions for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the Employees' Provident Funds Act, 1952 so that the benefits under the provident fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefit provided under the Employees' Provident Funds Act, 1952.

7. The establishment shall submit an audited balance sheet of its provident fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner within 3 months of the close of the year.

8. No amendment of the rules of the provident fund shall be made without the previous approval of the Central Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Central Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

[No. 11/19/68-PF.II.]

का० आ० 1940.—यतः मेसर्स निचिमेन कम्पनी लिमिटेड, 116, स्टेफन हाउस, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छूट देने के लिए आवेदन किया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय में अभिदाय की दरों की बाबत उक्त स्थापन के भविष्य निधि नियम उसके कर्मचारियों के लिए इन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं, और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाएं भी पा रहे हैं जो कर्मचारियों के लिए कुल मिला कर उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल नहीं हैं, जो, उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन दी जाती हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एतद्द्वारा छूट देती है और उक्त धारा 17 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि —

(क) उक्त स्थापन से सम्बन्धित नियोजक उक्त स्थापन के उन कर्मचारियों को, जो, यदि छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अधीन सदस्य हो गए होते, तत्समय देय वेतन के (आधारिक मजदूरी, महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो और उस पर अनुदेय खाद्य रियायत का नकद मूल्य) 0.09 (शून्य दशमलव शून्य नौ) प्रतिशत की दर से निरीक्षण-प्रभार मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि को देगी;

(ख) उक्त नियोजक भविष्य निधि अभिदायों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए निदेशों के अनुसार, विनिहित करेगा ।

अनुसूची

1. नियोजक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे विवरणियां भेजेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विहित करे ।

2. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को लेखा का वार्षिक विवरण या पास बुक भेजेगा ।

3. निधि की व्यवस्था, जिसमें लेखा रखना, लेखाओं और विवरणियों का भेजा जाना, संचयों का अन्तरण, निरीक्षण-प्रभार देना आदि सम्मिलित हैं, करने में हुए सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जाएगा तब कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य-मुख्य बातों का अनुवाद भी प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी निधि) या छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित होता है, तो नियोजक स्थापन की निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ही दर्ज करेगा और ऐसे कर्मचारी की बाबत उसके पिछले संचयों का स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा ।

6. यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए, जिसमें नियोजक का स्थापन जाता है, भविष्य निधि के अभिदायों की दर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन बढ़ा दी जाए तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधाएं उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हो जाएं जिनकी व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन है ।

7. स्थापन अपनी भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलन-पत्र हर वर्ष क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा ।

8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से यह सम्भावना हो कि उससे कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व, कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा ।

[सं० 11/19/68—पी०एफ० 2]

S.O. 1941.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harekrishna Rout and Raghunath Rout, 51/A, Circular Garden Reach Road, Calcutta-23 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1970.

[No. 3(256)/70-PF. II.]

का० आ० 1941.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स हरेकृष्ण रावत और रघुनाथ रावत, 51/ए, सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कलकत्ता-23 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 की जून के तीसवें दिन को प्रदत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या 8 (256)/70-पी०एफ० 2]

S.O. 1942.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment, known as Messrs Liberty Stores, Diamond Building, Hampankatta, Mangalore-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1970.

[No. 8(267)/70-PF. II.]

का० आ० 1942:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स लिबर्टी स्टोर्स, डायमण्ड बिल्डिंग, हम्पनकट्टा, मंगलौर-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के सितम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ;

[संख्या 8/267/70-पी०एफ०-2]

S.O. 1943.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. Parikh and Company, K. Parikh House, 47, P. D. Mello Road, Bombay-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1970.

[No. 8(250)/70-PF. II.]

का० आ० 1943:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स के० पारिख एण्ड कम्पनी, के० पारिख हाउस, 47, पी०डी० मैलो रोड, मुम्बई-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के अप्रैल, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8(250)/70-पी०एफ०-2]

S.O. 1944.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. G. Industries, Hanuman Silk Mills Compound, Agra Road, Bhandup, Bombay-78 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1970.

[No. 8(254)/70-PF. II.]

का० आ० 1944:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स एम०जी० इन्डस्ट्रीज, हनुमान सिल्क मिल्स कम्पाउन्ड, आगरा रोड, भान्दुप, मुम्बई-78 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8 (254)/70-पा०एफ०-2]

S.O. 1945.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B. K. Motors, 170, Lower Circular Road, Calcutta-14 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1969.

[No. 8(251)/70-PF. II.]

का० आ० 1945:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स बी०के० मोटर्स, 170, लोवर सर्कुलर रोड, कलकत्ता-14 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1969 के दिसम्बर, के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या 8(251)/70-पी०एफ०-2]

S.O. 1946.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment, known as Messrs Cochin Shipping Company, VI/26, Calvetty, Post Box No. 42, Cochin-1, Kerala State including its branch at Patva Chambers, 2nd Floor, Room No. 22, 104-108, Clive Road, Danabunder, Bombay-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment with effect from the 31st May, 1971.

[No. 8(296)/70-PF. II.]

का० आ० 1946:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स कोचीन शिपिंग कम्पनी, VI/26, कालवेट्टी, पोस्ट बाक्स संख्या 42, कोचीन-1, केरल राज्य नामक स्थापन, जिसमें इसकी पटवा चैम्बर्स, दूसरी मंजिल, कमरा 22, 104–108, क्लाइव रोड, दनबुन्देर, मुम्बई-9 स्थित शाखा सम्मिलित है, से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा 31 मई, से लागू करती है ।

संख्या 8(296)/70-पी० एफ०-2]

S.O. 1947.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Protection and Indemnity Services of India, India House, 4th floor, Opposite General Post Office, Bombay-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of May, 1970.

[No. 8(253)/70-PF. II.]

का० आ० 1947:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स प्रोटेक्शन एण्ड इंडेम्निटी सर्विसेज आफ इंडिया, इंडिया हाउस, चौथी मंजिल, जनरल पोस्ट आफिस के सामने, मुम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 की मई के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8 (253)/70—पी०एफ 2]

S.O. 1948.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The New Russian Automobiles, Mirzapur Road, Ahmedabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1968.

[No. 8(261)/70-PF. II.]

का० आ० 1948:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स दि न्यू० रसियन आटोमोबाइल्स, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1968 के अक्तूबर, के अकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएग।

[सं० 8 (261)/70—पी० एफ० 2]

S.O. 1949.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Natraj Talkies, Pratap Ganj, Baroda-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1968.

[No. 8(252)/70-PF. II.]

का० आ० 1949:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स नटराज टाकीज, प्रताप गंज, बड़ोदा—2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागु करती है ।

यह अधिसूचना 1968 के सितम्बर, के तीसवें दिन को प्रवत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8(252)/70—पी० एफ०—2]

S.O. 1950.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment, known as Messrs Dinesh Textile, Hiralal Colony, Ashwini Kumar Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1969.

[No. 8(246)/70-PF. II.]

का० आ० 1950:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स दिनेश टैक्सटाइल, हीरालाल कालोनी, अश्विनी कुमार रोड़, सूरत नामक स्थापन से समबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागु करती है ।

यह अधिसूचना 1969 के सितम्बर, के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या 8(246)/70—पी०एफ०—2]

S.O. 1951.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Enoch Pharma, Oliyakovil, Quilon-8 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment with effect from the 31st May, 1971.

[No. 8(276)/70-PFII.]

का० आ० 1951:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स इनोच फार्मा, ओलियाक्रोविल, क्वीलोन-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को 31 मई, 1971 से एतद्द्वारा लागू करती है।

[सं० 8/276/70-पी०एफ०-2]

S.O. 1952.—Whereas Messrs Getz Brothers and Company, Inc(9, Brabourne Road, Calcutta-1 (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952);

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act, and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees Provident Funds Sscheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme and in pursuance of sub-section (3) of the said section 17, the Central Government hereby directs that,—

(a) the employer in relation to the said establishment shall pay within fifteen days of the close of the month to the Employees' Provident Fund, inspection charges at the rate of 0:09 per cent (zero point zero nine per cent) of the pay (baic wages, dearness allowance, retaining allowance, if any, and cash value of food concession admissible thereon) for the time being payable to the employees of the said establishment who would have become members under the said scheme but for this exemption;

(b) the said employer shall invest the provident fund contributions in accordance with the directions issued by the Central Government from time to time.

THE SCHEDULE

1. The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government may, from time to time, prescribe.

2. The employer shall furnish to each employee an Annual Statement of Account or Pass Book.

3. All expenses involved in the administration of the Fund including the maintenance of accounts, submission of accounts and returns, transfer of accumulations, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Fund as approved by the appropriate Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee who is already member of the Employees' Provident Fund (Statutory Fund) or the Provident Fund of another exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Fund of the establishment, and accept the past accumulations in respect of such employee and credit to his account.

6. The employer shall enhance the rate of provident fund contribution appropriately if the rate of provident fund contributions for the class

of establishments in which his establishment falls is enhanced under the Employees' Provident Funds Act, 1952 so that the benefits under the provident fund scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefit provided under the Employees' Provident Funds Act, 1952.

7. The establishment shall submit an audited balance sheet of its provident Fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner within 3 months of the close of the year.

8. No amendment of the rules of the provident fund shall be made without the previous approval of the Central Provident Fund Commissioner. Where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Central Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

[No. 11/36/70-PF. II.]

का० आ० 1952.—यत: गेज ब्रास एण्ड कम्पनी, इन्क, 9 ब्रबर्न रोड़, कलकत्ता-1 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छूट देने के लिए आवेदन किया है ;

और यत: केन्द्रीय सरकार की राय में अभिदाय की दरों की बाबत उक्त स्थापन के भविष्य निधि नियम उसके कर्मचारियों के लिए उन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं, और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाएं भी पा रहे हैं जो कर्मचारियों के लिए कुल मिलाकर उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल नहीं हैं जो, उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन दी जाती है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एतद्द्वारा छुट देती है और उक्त धारा 17 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि :—

(क) उक्त स्थापन से सम्बद्ध नियोजक उक्त स्थापन के उन कर्मचारियों को, जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अधीन सदस्य हो गए होते, तत्समय देय वेतन के (आधारिक मजदूरी, मंहगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, और उस पर अनुज्ञेय खाद्य रियायत का नकद मूल्य) 0.09 (शुन्य दशमलव शुन्य नौ) प्रतिशत की दर से निरीक्षण-प्रभार मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर कमचारी भविष्य निधि को देगा;

(ख) उक्त नियोजक भविष्य निधि अभिदायों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए निदेशों के अनुसार, विनिहित करेगा।

अनुसूची

1. नियोजक केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे विवरणियां भेजेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विहित करे।

2. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा-विवरण या पास-बुक भेजेगा।

3. निधि के प्रशासन, जिसमें लेखाओं का बनाए रखना, लेखाओं और विवरणियों का भेजा जाना, संचयों का अन्तरण, निरीक्षण-प्रभारों आदि का संदाय सम्मिलित हैं, में अन्तर्वलित सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उन में संशोधन किया जाएगा तब कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य-मुख्य बातों का अनुवाद भी प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी, भविष्य निधि (कानूनी निधि) या छूट-प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित होता है तो नियोजक स्थापन की निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ही दर्ज करेगा और ऐसे कर्मचारी की बाबत उसके पिछले संचयों को स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा।

6. यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए, जिसमें नियोजक का स्थापन आता है, भविष्य निधि के अभिदायों की दर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन बढ़ादी जाए तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधाएं उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हो जाएं जिनकी व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन है।

7. स्थापन अपनी भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलन पत्र हर वर्ष केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा।

8. भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो वहां केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व, कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

[सं० 11/36/70-पी०एफ०-2.]

S.O. 1953.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), read with paragraph 27-A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby exempts the classes of employees constituting the Clerical including assistants, and subordinate staff of Messrs Indian Cable Company Limited, 9, Hare Street, Calcutta-1 who are in enjoyment of the said Company's Provident Fund benefits which are not less favourable than the benefits provided under the said Act and the Scheme, from the operation of all the provisions of the said Scheme, and directs that Messrs Indian Cable Company Limited shall pay to the Employees' Provident Fund, inspection charges at such rates as may be specified by the Central Government from time to time within 15 days of the close of each month and shall invest the provident fund contributions in respect of such classes of employees in such manner as the Central Government may direct from time to time.

[No. 11/58/67/PF-II.]

का० आ० 1953.—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27क के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारियों के उन वर्गों को, जिनमें मेसर्स इण्डियन केबिल लिमिटेड, 9, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता-1 के लिपिकीय कर्मचारी-वृन्द, जिसमें सहायक और अधीनस्थ कर्मचारी वृन्द हैं, आते हैं, और जो उक्त कम्पनी की भविष्य निधि की ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं जो उक्त अधिनियम और स्कीम के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एतद्द्वारा छूट देती है और निदेश देती है कि मैसर्स इंडियन केबिल कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी भविष्य निधि को निरीक्षण-प्रभार का सन्दाय

प्रत्येक मास के अन्त में 15 दिन के भीतर ऐसी दरों पर करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं और कर्मचारियों के ऐसे वर्गों के बारे में भविष्य निधि अभिदायों को ऐसी रीति से विनिहित करेगी जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

[संख्या 11/58/67-पी० एफ०-2]

S.O. 1954.—In pursuance of clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby appoints the Officer on Special Duty, Finance Department, Government of Uttar Pradesh, as a member of the Regional Committee for the State of Uttar Pradesh in place of the Deputy Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1703 dated the 29th June, 1960 namely:—

In the said notification, against item (3), for the entry "The Deputy Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department, Lucknow", the following entry shall be substituted, namely:—

"The Officer on Special Duty, (In-charge Provident Fund), Finance Department, Government of Uttar Pradesh Lucknow."

[No. 12(5)/64-PF. II.]

का० आ० 1954.—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उपपैरा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विशेषाधिकारी वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को उपसचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1703 तारीख 29 जून 1960 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, मद (3) के सामने प्रविष्ट "उपसचिव उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, लखनऊ," के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"विशेषाधिकारी (भारसाधक भविष्य निधि)
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।"

[सं० 12 (5)/64-पी० एफ० -2]

S.O. 1955.—Whereas Messrs Polydor of India Limited, Ashok Nagar, Kandivalee (East), Bombay-67 (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952);

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the prodident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act, and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme and in pursuance of sub-section (3) of the said section 17, the Central Government hereby directs that.—

(a) the employer in relation to the said establishment shall pay within fifteen days of the close of the month to the Employees' Provident Fund, inspection charges at the rate of 0.09 per cent (zero point zero nine per cent) of the pay (basic wages, dearness allowance, retaining allowance, if any, and cash value of food concession admissible thereon) for the time being payable to the employees of the said

establishment who would have become members under the said Scheme but for this exemption;

(b) the said employer shall invest the provident fund contributions in accordance with the directions issued by the Central Government from time to time.

THE SCHEDULE

1. The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government may from time to time, prescribe.

2. The employer shall furnish to each employee an Annual Statement of Account or Pass Book.

3. All expenses involved in the administration of the Fund including the maintenance of accounts, submission of accounts and returns, transfer of accumulations, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Fund as approved by the appropriate Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee who is already member of the Employees' Provident Fund (Statutory Fund) or the Provident Fund of another exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Fund of the establishment, and accept the past accumulations in respect of such employee and credit to his account.

6. The employer shall enhance the rate of provident fund contribution appropriately if the rate of provident fund contributions for the class of establishment in which his establishment falls is enhanced under the Employees' Provident Funds Act, 1952 so that the benefits under the provident fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefit provided under the Employees' Provident Funds Act, 1952.

7. The establishment shall submit an audited balance sheet of its provident fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner within 3 months of the close of the year.

8. No amendment of the rules of the provident fund shall be made without the previous approval of the Central Provident Fund Commissioner, where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Central Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

[No. 11/34/70-PF. II.]

का०आ० 1955:—यतः मैसर्स पोलीडोर ग्राफ इंडिया लिमिटेड, अशोक नगर, कण्डीवाली (पूर्व) मम्बई-67 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छूट देने के लिए आवदन किया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय में अभिदाय की दरों की बाबत उक्त स्थापन के भवष्य निधि नियम उसके कर्मचारियों के लिए उन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं, और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाएं भी पा रहे हैं जो कर्मचारियों के लिए कुल मिलाकर उन प्रसुविधाओं से कम अनकूल नहीं हैं, जो उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के संबन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 (जिसें इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहां गया है) के अधीन दी जाती है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन

रहते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एतद्द्वारा छूट देती है और उक्त धारा 17 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि:—

(क) उक्त स्थापन से सम्बन्ध नियोजक उक्त स्थापन के उन कर्मचारियों को, जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अधीन सदस्य हो गए होते, तत्समय देय वेतन के (आधारित मजदूरी, मंहगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, और उस पर अनुशय खाद्य रियायत का नकद मूल्य) 0.09 (शून्य दशमलव शून्य नौ) प्रतिशत की दर से निरीक्षण प्रभार मासन्त के पन्द्रह दिन के भीतर कर्मचारियों भविष्य निधि को देगा ;

(ख) उक्त नियोजक भविष्य निधि अभिदायों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए निदेशों के अनुसार विनिहित करेगा ।

अनुसूची

1. नियोजक प्रादेशिक / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे विवरणियां भेजेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय समय पर विहित करे ।
2. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा-विवरण या पास बुक भेजेगा ।
3. निधि के प्रशासन जिसमें लेखाओं का बनाए रखना, लेखाओं और विवरणियों का भेजा जाना ; संचयों का अन्तरण, निरीक्षण-प्रभारों आदि का संदाय सम्मिलित हैं, में अन्तर्वलित सभी व्यय का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
4. नियोजक समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रतिस्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जाएगा तब कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य मुख्य बातों का अनुवाद भी प्रदर्शित करेगा ।
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी निधि) या छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित होता है तो नियोजक स्थापन की निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ही दर्ज करेगा और ऐसे कर्मचारियों की बाबत उसके पिछले संचयों को स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा ।
6. यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए, जिसमें नियोजक का स्थापन आता है, भविष्य निधि के अभिदायों की दर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन बढ़ा दी जाए तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधाएं उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हो जाएं जिनकी व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन है ।
7. स्थापन अपनी भविष्य निधि का संपरीक्षित तलन-पत्र हर वर्ष प्रादेशिक/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वर्तमान वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा ।
8. भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा । जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो वहां प्रादेशिक/केन्द्रीय भविष्य

निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा।

[सं० 11/34/71-पी० एफ० II]

S.O. 1956.—In pursuance of clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, the Central Government hereby appoints the Joint Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Finance Department, as a member of the Regional Committee for the State of Andhra Pradesh and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Department of Social Security No S.O. 1294, dated the 8th April, 1965, namely:—

In the said notification against Serial No. 3, for the existing entry in the first column, the following entry shall be substituted, namely:—

"The Joint Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Finance Department, Hyderabad."

[No. 12/1/68-PF. II.]

का० आ० 1956.—कर्मचारी भविष्यनिधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप पैरा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार संयुक्त सचिव वित्त विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य की प्रदेशिक समिति का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भतपूर्व समाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 1294 तारीख 8 अप्रैल, 1965 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 3 के सामने, प्रथम स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात

"संयुक्त सचिव वित्त विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।"

[सं० 12/1/68-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 30th April 1971

S.O. 1957.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri S. L. Tewari to be an Inspector for the whole of the State of Uttar Pradesh for the purposes of the said Act and of any Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil-field or a controlled industry.

[No. 21(4)/68-PF.I.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1971

का० आ० 1957—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० एल० तिवारी को, उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कंपनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, निरीक्षक, नियुक्त करती है।

[सं० 21 (4)/68-पी० एफ०-1]

दलजीत सिंह, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 27th April 1971

S.O. 1958.—Whereas the Central Government is of opinion that the minimum rates of wages should be fixed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in respect of employment in Asbestos Mines covered under the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment to Part I of the Schedule to the said Act.

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition on or before the 5th August, 1971 will be considered by the Central Government.

[No. LWI-I-2 (15)/67-WE(MW).]

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 1971

का० आ० 1958:—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) के अन्तर्गत आने वाली ऐस्बेस्टास खानों में नियोजन की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन नियत की जानी चाहिए ;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 में उक्त नियोजन को जोड़ने के अपने आशय की सूचना देती है ।

उक्त जोड़ने के बारे में जो आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से 5 अगस्त, 1971 को या उससे पूर्व प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

[सं० एल० डब्ल्यू० आई० 1-2 (15)/67-डब्ल्यू०ई० (एम०डब्ल्यू०)]

हंस राज छाबड़ा, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 28th April 1971

S.O. 1959.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Marine Colliery of Messrs New Marine Coal Company (Bengal) Private Limited, Post Office Kusunda, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd April, 1971.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

REFERENCE NO. 65 OF 1968

PARTIES:

Employers in relation to the New Marine Colliery of Messrs New Marine Coal Company (Bengal) Private Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad

AND

Their Workmen

PRESENT:

Shri A. C Sen, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate with Shri P. K. Bose, Advocate.

For the Workmen—Shri Lalit Burman, General Secretary, Bihar Koyla Mazdoor Sabha.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, dated the 12th April, 1971

AWARD

The Central Government by its Order No. 2/64/68-LRII dated, New Delhi, the 24th July, 1968 passed in exercise of the power conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute between the parties above named to this Tribunal for adjudication,

"Whether the dismissal from service of Shri Binu Dusadh, Trammer, with effect from the 19th February, 1968 by the management of New Marine Colliery of Messrs New Marine Coal Company (Bengal) Private Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The said order was received by this Tribunal on 20th August, 1968 The written statement on behalf of the workmen was filed on 8th October, 1968 and the written statement-*cum*-rejoinder on behalf of the employers was filed on 17th October, 1968.

3. The concerned workman was an employee of the Kirkend Colliery which was taken over in 1967 by the management of Messrs New Marine Coal Co. (Bengal) Private Ltd.

4. In para 2 of the workmen's written statement it has been said that the workman concerned had been working as a Pump/Tugger Khalasi continuously till he was reverted to the post of the underground trammer by the new management sometime after its take over in 1967 and that he took up the work of the underground trammer under protest. The employers have stated in their written statement-*cum*-rejoinder that the workman concerned worked as a Pump/Tugger Khalashi against casual vacancies but that he was paid wages of a trammer which was his substantive post and they have denied that he was reverted to the post of a trammer by the new management sometime after the take over in 1967 or that there was any protest by him.

5. It is the common case that the workman concerned took his annual leave from 8th January, 1968 and after the expiry of the leave period reported for duty on 16th January, 1968. According to the workman, he was not allowed to join his duty in the post of the underground trammer on 16th January, 1968 and he was verbally asked by the Colliery Manager to join work as surface trammer. The employers' version is that when the workman concerned returned from leave on 16th January, 1968 there was no work of trammer underground due to reduced working and that, therefore, he was provided with the trammers' job on the surface.

6. According to the workmen, the workman concerned immediately pointed out that if he worked as trammer on the surface that would adversely affected him; however, on being assured by the manager that it was just for a week and that his interest would not be adversely affected, he joined as a surface trammer. This part of the workmen's story has been categorically denied by the employers in their written statement.

7. It has been stated in para 5 of the workmen's statement that contrary to the assurance given by the Manager on 16th January, 1968, the workman concerned was not allowed to work as an underground trammer from the next week commencing from 22nd January, 1968 and that he was forced to continue to work as a surface trammer. According to the management, as no assurance was given by the Manager on 16th January, 1968 or on any other date, the question of forcing the workman concerned to work as trammer on the surface does not arise.

8. The genesis of the present dispute is an incident that took place on 27th January, 1968. The version of the workmen about this incident as given in para 6 of their statement is as follows: "That on 27th January, 1968 the workman was paid less amount than his usual earnings as the underground allowance was deducted by the management. When the workman (concerned) went to represent his grievances to the Manager, he was badly treated, turned out of the office and was assaulted by some of the stooges of the management right in front of the colliery office. The version of the management, as given in para 7 of their statement-*cum*-rejoinder, is as follows:—".....that since Shri Dushad did not work as a trammer underground he was not entitled to any underground allowance and as such the allegation of deduction from the earnings is baseless. The allegation that he was badly treated and was assaulted when he went to represent his grievances to the manager.....are false and baseless and are denied".

9. It is stated in para 7 of the workmen's statement that thereafter the management instead of doing justice to the workman concerned suspended him with effect from 29th January, 1968 by a letter embodying the charge-sheet, dated 29th January, 1968 charging him with disorderly behaviour and that the workman in his reply denied the charge stating the correct facts.

10. As to the enquiry on the basis of the charge-sheet the version of the workmen as given in para 8 of their statement is as follows: "That the management proposed to hold an enquiry on 5th Febuary, 1968. But there was no enquiry worth the name, and neither any witness was examined in the workmans' presence nor the workman was allowed any reasonable and proper opportunity of his defence. The Enquiry Officer took the statement of the workman and concluded the enquiry. Thus there was no just and proper enquiry at all".

11. The version of the management, as given in para 10 of their statement is as follows: "That a departmental enquiry was held on 5th February, 1968 in presence of Shri Binu Dushad when he was given full chance and opportunity to cross-examine the managements' witness and to produce the defence witnesses. That it may be mentioned that Shri Binu Dushad refused to put his thumb impression or signature on the statement of the managements' witnesses taken before him excepting his own statement. He however did not produce any witness in his defence".

12. The primary thing for consideration is whether the workman concerned got adequate opportunity to defend himself to cross-examine the witnesses examined by the management and to produce his own witness. The Manager of the colliery has examined himself. He says in his examination-in-chief that a departmental enquiry was held into the chargesheet by P. S. Sinha, the than Assistant Manager of the colliery on 5th February, 1968, that he was present at the enquiry proceeding, that the enquiry proceedings were written out by the enquiry officer in his presence, that he signed after his deposition had been recorded by the enquiry officer, that F. M. Jha and Dip Narayan Pathak deposed as witnesses at the enquiry on behalf of the management, and that the workman concerned gave his thumb impression in his presence during the course of the enquiry proceeding. The only suggestion made to him in cross-examination was that the enquiry proceeding from pages 1 to 7 were not genuine and he categorically denied the suggestion There was particularly no cross-examination as to that part of the deposition of the manager which deals with the factum of the departmental enquiry.

13. The workman concerned as WW1 has admitted in his cross-examination that he was asked to attend the enquiry proceedings, that he deposed on his behalf, that he did not produce any defence witness and that to his knowledge the enquiry was conducted. He has further stated that he does not know if the manager or F. M. Jha or B. N. Pathak deposed at the enquiry for the management. He did not produce any defence witness says he, as he was not asked to do so.

14. The evidence of the manager leaves no room for doubt that the departmental enquiry did take place on 5th February, 1968, that the workman concerned took part in the enquiry, that three witnesses including the manager deposed on behalf of the management and that the workman concerned was the only witness examined on his behalf. The documentary evidence clearly shows that the workman was given every opportunity to defend himself and to cross-examine the witnesses on behalf of the management. The enquiry proceedings have been marked as Ext. M6. Ext. M6(2) is the endorsement at the end of the manager's deposition by the enquiry officer to the following effect: "Sri Binu Dushad was explained the contents of the above statement in Hindi and he was asked to cross-examine the manager. He declined to put any question and also declined to put his signature or thumb impression". Ext. M6(5) shows that Binu Dushad refused to cross-examine F. M. Jha and Ext. M6(8) shows that he also refused to cross-examine Dip Narain Pathak. Ext. M6(10) is another endorsement on the enquiry proceedings (Ext. M6) over the thumb impression of Binu Dushad and the signature of the enquiry officer, it runs thus: "The reply I have given in reply to charge sheet issued to me is my statement and nothing more I have to add. And I have no witness to produce in my defence".

15. From Exts. M6 series it is clear that though Binu Dushad was given full opportunity to cross-examine the witnesses of the management and to produce his own witnesses, he did not avail of that opportunity. The facts stated in his reply to the charge sheet should have been narrated before the enquiry officer, because the enquiry officer was not expected to know the contents of the reply given by Binu Dushad to the management. It is for this reason that the enquiry officer did not ask the management to cross-examine Binu Dushad. There is nothing in the enquiry proceedings to show the management was asked to cross-examine Binu Dushad.

16. From the evidence on record I am satisfied that a proper departmental enquiry was held and that Binu Dushad was given adequate opportunity to defend himself. Mr. Burman, appearing on behalf of the workman argues that Binu Dushad was examined not on 5th February, 1968 but on 8th February, 1968, and in support of this argument he refers to the dates given in the enquiry proceedings at the end of the deposition of Benu Dushad. Those two dates have been marked as Exts. M6(10) and M6(11). According to him, these two dates as written by the enquiry officer, should be read as 8th February, 1968 and not 5th February, 1968. But I have no doubt in my mind that these two dates are 5th February, 1968 and not 8th February, 1968. Moreover, it has been admitted in the written statement of the workmen that the management proposed to hold an enquiry on 5th February, 1968. It is not the workmen's case that Binu Dushad attended the enquiry not on the date proposed but on some other date. Therefore, there is no substance in the argument of Mr. Burman that Binu Dushad was examined on 8th February, 1968, whereas the witnesses on behalf of the management were examined, if at all, on 5th February, 1968.

17. The enquiry officer submitted a report to the manager containing the result of his enquiry. The report has been marked as Ext. M7. He discussed the evidence in details. He also took into consideration the reply given be Binu Dushad in reply to the charge sheet. He found him guilty of the charge of disorderly conduct levelled against him. His finding could in no way be said to be perverse and it was supported by the evidence on record. I cannot go behind the findng which is fair and fully supported by evidence.

18. In the written statement of the workmen the management and its officials have been accused of disorderly behaviour and arbitrary actions; but these charges against the management and its officials are not borne out by the materials on record. In his reply to the charge sheet (Ext. M2) the workman concerned stated as follows: "On 27th January, 1968 after getting the wages I found that the underground allowance was not paid contrary to your assurance. I, therefore, went to you to again represent my case. But instead of hearing my genuine complaint you shouted me down and called the charprasis. Before I could realise what happened one Pathak, Jha and Harihar caught hold of me and assaulted me in your presence while pushing me out. Outside the office I was again beaten by Jha with shoes. Thus I was not guilty of any disorderly behaviour. I went to you to represent my grievances in an orderly manner but I was humiliated and assaulted in your presence". Pathak and Jha deposed at the enquiry proceeding in the presence of Binu Dushad. They categorically denied that they had assaulted Binu Dushad. But Binu Dushad refused to cross-examine them. Therefore his allegation that he was assaulted in the presence of the manager on 27th January, 1968 is baseless. Before this Tribunal Binu Dushad has stated as follows in his examination in chief: I went to the manager with only my wages in my hand

because the amount was less than my normal wages.....The manager told me that you would get the underground allowance.....when I was representing my case manager called out chaprasis, then Shri Pathak, Pump Khalasi/chaprasi, Jha, Loading-in-Charge and Harihar, Chaprasi came in and pushed me out of the office and I was assaulted with shoes by Jhaji....." I am not inclined to attach any importance to this part of his evidence as he failed to lead evidence on this point before the domestic tribunal, where every opportunity was given to him to defend himself and to cross-examine the witnesses of the management. Where an enquiry is fairly conducted the charge-sheeted workman cannot be allowed to improve his case before the Tribunal. In this connection reference may be made to the following observation of the Supreme Court in Tala Oil Mills Co. v. Its Workmen, (1964) II L.L.J. 113 at 119: "But if the enquiry has been fairly conducted, it means that all reasonable opportunity has been given to the employee to prove his case by leading evidence. In such a case, how can the court hold that merely because the witnesses did not appear to give evidence in support of the employees' case, he should be allowed to lead such evidence before the industrial tribunal? If this plea is upheld, no domestic enquiry would be effective and in every case, the matter would have to be tried afresh by the industrial tribunal.

19. The plea of victimisation and unfair labour practice taken by the workman in their written statement is not supported by the materials on record. Moreover, before the domestic tribunal no such plea was taken. This plea was not taken by Binu Dushad even in his reply to the charge-sheet.

20. Mr. Burman on behalf of the workmen was anxious to establish that he was underground trammer and that he was entitled to get underground allowance even when he worked on the surface. But even assuming that he was paid less than what was his due and that he was unjustly disallowed underground allowance, that was no justification for his disorderly conduct before the Manager.

21. The employer have adopted the model standing order for the coal-mining industry. Standing Order No. 18(iv) laying down the duty of the punishing authority reads as follows:

> "In awarding punishment under the standing order, the authority awarding punishment shall take into account the gravity of the misconduct, the previous record, if any, of the workmen and any other extenuating or aggravating circumstances that may exist".

In the instant case the gravity of the misconduct has duly been taken into consideration. It is not easy to appreciate the meaning of the expression "the previous record, if any". Difficulty is created by the words "if any". An employee who has served for some time must have a previous record; then, what is the significance of the qualifying words "if any". These words imply that there may be an employee without any previous record. Next question that presents itself is: previous record of what is to be taken into consideration? Is it the previous record of misconduct, or the previous record of meritorious conduct? Then, for what purposes are extenuating or aggravating circumstances to be taken into consideration? Is it for awarding any punishment at all, or for awarding severe or light punishment? In my opinion, it is very difficult to find satisfactory answers to the various questions indicated above. This rule, in any event, appears to be recommendatory, rather than mandatory, inspite of the use of the word "shall". An employer is entitled to punish, whenever the alleged misconduct is established. It is for the employer to decide what kind of punishment is to be awarded, severe or light. In my opinion, a punishment awarded on proof of a misconduct is not liable to be set aside simply on the ground that there is nothing in record to show that the punishing authority has taken into consideration the previous record of the employee and other extenuating or aggravating circumstances. Standing order No. 18(i) provides that a workman may be suspended or fined or his increment may be stopped or he may be demoted or dismissed without notice, if he is found to be guilty of misconduct. In my opinion it is not for the Tribunal to say that in a particular case the employer instead of dismissing the employee should have awarded him a less severe punishment. Hence in the instant case the order of dismissal cannot be challenged on the ground that the punishment is too severe.

22. The above discussion leads to the conclusion that the dismissal from service of Binu Dusadh from the 19th February, 1968 by the management of New Marine colliery of Messrs New Marine Coal Co. (Bengal) Private Ltd., was justified and that the workman concerned is not entitled to any relief. I award accordingly.

23. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) A. C. SEN,
Presiding Officer.
[No. 2/64/68-LRII.]

New Delhi, the 3rd May, 1971

S.O. 1960.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Chirimiri Colliery, Post Office Galahpani, District Surguja (Madhya Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-*CUM*-LABOUR COURT, JABALPUR.

Dated March 25, 1971.

PRESENT:

Shri M. Chandra—*Presiding Officer.*

CASE REF. No. CGIT/LC(R)(16) OF 1970.

PARTIES:

Employers in relation to the management of North Chirimiri Colliery, Post Office Galahpani, District Surguja (Madhya Pradesh) and their workmen represented by Azad Koila Shramik Sabha Post Office Jhagrakhand Colliery, Distt. Surguja (M.P.)

APPEARANCES:

For workmen.

1. Sri B. Boral for Azad Koila Shramik Sabha.
2. Sri Gulab Gupta for M.P. Colliery Workers Federation.

For employers.

1. Sri P. S. Nair, Advocate.
2. Sri S. B. Mishra.

Industry: COAL MINE. *District:* SURGUJA (M.P.)

AWARD

By an order No. 8/183/70-LRII dated 10th November, 1970 the Government of India has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:—

Dispute

"Whether the management of North Chirimiri Colliery is justified in not granting sick leave with full wages for 15 days in a year to its workmen? If not, to what relief are the workmen entitled?"

The Central Wage Board recommended that all the workmen would be entitled to 15 days leave in a year on full pay or 30 days in a year on half pay with a right to accumulate sick leave for a period of 60 days and 120 days respectively in the entire period of service. The workmen alleged that the employer granted 15 days sick leave with full pay to the workmen of this colliery upto 1968 and then all of a sudden switched over to a new system of allowing only 30 days sick leave on half pay. While changing the service conditions the management did not, according to the workmen, care to follow the provisions of the Industrial Disputes Act and gave no notice under Section 9A of the Industrial Disputes Act. According to the workmen, the Central Wage Board also said that where there were provisions for sick leave more favourable than what was recommended by the Wage Board they should be binding on it and thus the management disregarded this recommendation and deprived the workmen of their long enjoyed benefits. The workmen claimed the restoration of the existing benefits.

The employers contended that the recommendations of the Wage Board is only recommendatory and cannot be equated with the terms of service conditions between the employers and the workmen. The employers also alleged that the new system of sick leave was in tune with the long past practice of the colliery. Even though at the time of initial implementation of the Wage Board recommendation the employers adopted the system of 15 days sick leave in a year on full

pay they reverted to the old system after giving due notice on 15th January, 1969. The employers have also sought to justify the adoption of the system of giving 30 days sick leave in a year on half pay.

The parties have now settled the matter amicably. The employers and their workmen represented by M. P. Colliery Workers Federation, Chirimiri and Azad Koila Shramik Sabha, Jhagrakhand Colliery have arrived at a compromise. It gives the workmen the right to sick leave upto a maximum of 10 days on full pay and thereafter 10 days sick leave on half pay in a calendar year. This sick leave is to be availed of only for sickness beyond 24 hours duration. Sick leave for sickness in the colliery is to be granted only when the application is supported by the certificate of the Colliery Medical Officer or by the Medical Officer Incharge of Regional Hospital Kurasia. In the case of sickness away from the colliery while on privilege or other leave, the workman is to be entitled to a sick leave for a maximum of 10 days only with half pay per year for all workmen provided that the application for sick leave is supported by a certificate from a Registered Medical Practitioner and the Mukhiya Surpanch of the Gram Panchayat at village Union Board. Total leave to which a worker is entitled in the event of sickness at Colliery is to be 10 days with full pay followed by 10 days with half pay. The entitlement of 10 days half pay may be availed of upon completion of necessary requirement outside the colliery also. This scheme of sick leave shall have effect from 1st January, 1971

The compromise is just, fair and proper for both the parties. An award is, therefore, made in terms of the compromise, which shall form part of the award. Two copies of the same compromise have been filed—one between the Management and Azad Koila Shramik Sabha and the other between the Management and the M.P. Colliery Workers Federation. The two copies of the same compromise are Annexures I and II to the award. As agreed to between the parties they will bear their own costs. Let the Award be sent to the Government.

Sd/- M. CHANDRA,
Presiding Officer,
25-3-1971.

ANNEXURE I

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL *CUM* LABOUR COURT AT JABALPUR, (M.P.).

REFERENCE No. CGIT/LC(R)/16/70

PARTIES :

Employers in relation to North Chirimiri Colliery of Messrs United Collieries Limited

AND

Their workmen represented by Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation, Chirimiri.

Petition

The parties above mentioned, without prejudice to their respect stands, have after mutual discussions resolved the dispute under reference on the following terms:

Terms of Settlement

1. It is agreed that all workmen, shall be entitled to a maximum of 10 days sick leave on full pay and thereafter 10 days sick leave on half pay in a calender year.

2. It is agreed that sick leave shall be availed only for sickness beyond 24 hours duration.

3. It is agreed that sick leave for sickness at the Colliery shall be granted only when the application for sick leave is supported by the certificate of the Colliery Medical Officer or be the Medical Officer-in-charge of Regional Hospital, Kurasia.

4. It is agreed that where sick leave is requested for sickness away from the colliery while on privilege or other leave, the entitlement for sick leave shall be upto a maximum of 10 days sick leave with half pay per year for all workmen, provided the application for sick leave is supported by a certificate from a Registered Medical practitioner and the Mukhiya Sarpanch of the Gram Panchayat at Village Union Board.

5. It is agreed that this scheme of sick leave will have effect from 1st January, 1971.

(Clarification: Total leave entitlement of a worker is 10 days with full pay followed by 10 days with half pay in he event of sickness at Colliery. The entitlement of 10 days half pay may be availed of upon completion of necessary requirements outside the Colliery also if necessary).

6. It is agreed that parties will bear their own costs.

Prayer

It is, therefore, prayed jointly by the parties that your honour may graciously be pleased to accept this settlement as fair and reasonable and to pass an award in terms thereof.

And for this act of kindness your humble petitioners shall, as in duty bound ever pray.

(Sd.) JITENDRA KUMAR,
23-3-71
Manager, North Chirimiri
Colliery of M/s United
Collieries Limited.
P.O. Galahpani, Distt. Surguja,
(Madhya Pradesh).

(Sd.) R M. SEN.
Vice President,
M. P. C. W. Federation,
Chirimiri (M.P.).

(Sd.) SAHEB RAJ SINGH,
23-3-71
President, North
Chirimiri Colliery
Branch of M.P.C.W.F.,
P.O. Galahpani (M.P.)

North Chirimiri Colliery,
23*rd March*, 1971.

Filed & verified by Sri P. S. Nair, Advocate and Shri J. Kumar, Manager (identified by Shri P. S. Nair).

(Sd.) M. CHANDRA,,
25-3-71.
Presiding Officer.

(Sd.) J. Kumar,
25-3-71

(Sd.) P S. Nair,
25-3-71

Verified by Shri Gulab Gupta, Advocate for the Union (M.P. Colliery Workers Federation).

(Sd.) M. CHANDRA,
25-3-71
Presiding Officer.

PART OF AWARD

(Sd.) M. CHANDRA,,
Presiding Officer.

ANNEXURE II

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL *CUM* LABOUR COURT AT JABALPUR. (M.P.).

REFERENCE NO. CGIT/LC(R)/16/70

PARTIES:

Employers in relation to North Chirimiri Colliery of Messrs United Collieries Limited

AND

Their workmen represented by Azad Koila Shramik Sabha, Post Office Jhagarakhan Colliery, District Surguja (Madhya Pradesh).

Petition

The parties above mentioned, without prejudice to their respective stands, have after mutual discussion resolved the dispute under reference on the following terms:

Terms of Settlement

1. It is agreed that all workmen, shall be entitled to a maximum of 10 days

sick leave on full pay and thereafter 10 days sick leave on half pay in a calender year.

2. It is agreed that sick leave shall be availed only for sickness beyond 24 hours duration.

3. It is agreed that sick leave for sickness at the Colliery shall be granted only when the application for sick leave is supported by the certificate of the Colliery Medical Officer or by the Medical Officer-in-charge of Regional Hospital, Kurasia.

4. It is agreed that where sick leave is requested for sickness away from the colliery while on privilege or other leave, the entitlement for sick leave shall be upto a maximum of 10 days sick leave with half pay per year for all workmen, provided the application for sick leave is supported by a certificate from a Registered Medical practitioner and the Mukhiya Sarpanch of the Gram Panchayat at Village Union Board.

5. It is agreed that this scheme of sick leave will have effect from 1st January, 1971.

(Clarification: Total leave entitlement of a worker is 10 days with full pay followed by 10 days with half pay in the event of sickness at Colliery. The entitlement of 10 days half pay may be availed of upon completion of necessary requirements outside the Colliery also if necessary).

6. It is agreed that parties will bear their own costs.

Prayer

It is, therefore, prayed jointly by the parties that your honour may graciously be pleased to accept this settlement as fair and reasonable and to pass an award in terms thereof.

And for this act of kindness your humble petitioners shall, as in duty bound ever pray.

(Sd.) JITENDRA KUMAR,
23-3-71
Manager, North Chirimiri
Colliery of M/s. United
Collieries Limited,
P.O. Galahpani, Distt Surguja
(Madhya Pradesh).
North Chirimiri Colliery,
23rd *March*, 1971.

(Sd.) B BORAL,
23-3-71
General Secretary,
Azad Koila Sharmik Sabha,
Post Office Jhagarakhan
Colliery, District Surguja
(M.P.)

Filed verified by Sri P. S. Nair, Advocate and Sri J. Kumar, Manager (identified by Sri P. S. Nair) for the Management by Sri B. Boral (identified by Sri P. S. Nair) for the Azad Koila Shramik Sabha.

(Sd.) M. CHANDRA,,
25-3-71

Sd./- B. BORAL,
25-3-71.
Sd./- J. KUMAR,
25-3-71.
Sd./- P. S. NAIR,
25-3-71.

Part of Award

(Sd.) M. CHANDRA,,
Presiding Officer.
[No. 8/183/70-LR.II.]

ORDER

New Delhi, the 28th April 1971

S.O. 1961.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs B. Patnaik Mines (Private) Limited, Barbil and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the termination of services of Smt. Sabita Kachhap, Creche-Nurse in the Barpada Iron Mines by the management of Messrs B. Patnaik Mines (Private) Limited, with effect from the 31st August, 1969 is justified? If not, to what relief is Smt. Sabita Kachhap entitled?

[No. 12/8/70-LRIV.1]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1971

का० आ० 1961.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स बी० पटनायक माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बार्बिल के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), धनबाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स बी० पटनायक माइन्स (प्राइवेट-लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र द्वारा बारपापादा आयरन माइन्स में श्रीमती सबिता कच्छप, बालगृह नर्स की सेवाओं को 31 अगस्त, 1969 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो श्रीमती सबिता कच्छप किस अनुतोष की हकदार हैं ?

[सं० 12/8/70-एल० आर०-4]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

[Office of the Chief Labour Commissioner (Central)]

ORDER

New Delhi, the 15th April 1971

S.O. 1962.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Chairimiri Colliery Company Pvt. Ltd. (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for further extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 30th June, 1970.

An whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB. 20(42)/65 dated the 28th August, 1965, and in partial modification of my order No. BA-5(2)/71-LS. I, dated 18th February, 1971, passed order on 13th April, 1971, extending the period for payment of the said bonus by the said employer by a total period of four months (i.e. up to 30th June, 1971) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s):	*Establishment(s)*
M/s. Chirimiri Colliery Company Pvt. Ltd. P.O. Box No. 2256, 18/22, Sheikh Memon Street, Bombay-2.	Chirimiri Colliery, Chirimiri Distt. Surguja. (M.P.).

[No. BA-5(2)/71-LS. I.]

O VENKATACHALAM,
Chief Labour Commissioner (Central).

(श्रम और रोजगार विभाग)

[मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय]

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल 1971

एस० ओ० 1962.—मैसर्स चिरिमिरी कोलयरी कं० प्रा० लि० (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के सम्बन्धों मे 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को और अधिक बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19 (ख) के अधीन आवेदन दिया है ।

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी-20(42)/65, तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने आदेश सं० बी० ए० 5(2)/71 एल० एस० 1, ता० 18 फरवरी, 1971 के आंशिक संशोधन में ता० 13 अप्रैल, 1971 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से कुल 4 महिने (अर्थात 30-6-1971 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है ।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता :	स्थापन :
मैं० चिरिमिरी कोलयरी कं० प्रा०लि०, पो० बौक्स नं 2256, 18/22, शेख मेमन स्ट्रीट, बम्बई-2 ।	चिरिमिरी कोलयरी, चिरिमिरी, जि० सरगुजा-म० प्र०

[सं० बी०ए०-5(2)/71-एल०एस० 1]

ओ० वेंकटाचलम,
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 24th April 1971

S.O. 1963.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Sahukara Bank Ltd., Ludhiana, in respect of the plot of land held by it at Banga, Jullundur District, Punjab, till the 15th March, 1972.

[No. F. 15(10)-BC/71.]

K. YESURATNAM, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1963—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 के दसवें) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध साहूकारा बैंक लिमिटेड, लुधियाना पर, बांगे जिला जालन्धर, पंजाब में उक्त बैंक द्वारा धारित भू-खण्ड (प्लाट आफलैड) के सम्बन्ध में, 15 मार्च, 1972 तक लागू नहीं होंगे।

[संख्या एफ० 15(10) बी०-सी० 71]

के० येसुरत्नम, अनुसचिव।

(Department of Banking)

New Delhi, the 28th April 1971

S.O. 1964.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government nominates Shri L. D. Kataria, Deputy Secretary, Ministry of Finance (Department of Banking), in consultation with the State Bank of India, to be a Director of the State Bank of Patiala, *vice* S. R. Wadhwa.

[No. F.2(3)PSB-SB/71.]

D. K. SEN, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1971

एस०ओ० 1964.—स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का अड़तीसवां) की धारा 25 की उप-धारा 2 (1) के खण्ड (ङ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए, केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) के उप-सचिव श्री एल० डी० कटारिया को, श्री एस० आर० वाधवा के स्थान पर स्टेट बैंक आफ पटियाला का निदेशक नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 2(3)-पी०एस० बी०-एस० बी०-71]

डी० के० सेन, अवर सचिव।

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE, SHILLONG

CENTRAL EXCISE

Shillong, the 20th February 1971

S. O. 1965.—In exercise of the powers exercised under section 2(a) of the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966) the power of the Collector under various sections of the Produce Cess Act, 1966 are delegated to the Central Excise Officer as under. The Collectorate Notification No. 1/70, dated 25-2-70 may be treated as modified to this extent.

TABLE

Relevant section of the Produce Cess Act, 1966	In regard to	Officers of Central Excise to whom the powers are proposed to be delegated
	2	3
1. 7	Furnishing particulars about the Mill.	Superintendent of Central Excise.
2. 8	Submission of monthly returns.	Do.
3. 9(1) & (2) . .	Collection of Cess . .	Do.
4. 12(a) (b) (c) .	Recovery of sum due . .	Do.
5. 13(1) & (2) .	Powers to inspect mills etc. .	Officers not below the rank of Inspectors of Central Excise.
6. 16 . . .	Adjudication of offences etc. .	Assistant Collector of Central Excise.
7. 18 . . .	Composition of offences .	Do.

[No. 1/71]

A. K. BANDYOPADHYAY,
Collector,
Customs & Central Excise, Shillong.

केन्द्रीय उत्पाद व आबकारी समाहर्ता का कार्यालय शिलांग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

शिलांग, 20 फरवरी, 1971

एस० ओ० 1965—उत्पादन चुंगी अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की धारा 2 (ए) में कलक्टर को दी गई शक्तियों को कलक्टर उत्पादन चुंगी अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं को निम्न रूप से केन्द्रीय शुल्क के अफसर को सौंपते हैं। कलक्टरेट की अधिसूचना सं० 1/70, दिनांक 25-2-70 यहां तक संशोधित माना जाये।

सारिणी

उत्पादन चुंगी अधिनियम, 1966 से संबंधित धारा	किस बारे में	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अफसर जिन्हें अधिकारों के सौंपने का निर्णय लिया गया
1	2	3
1.	7 मिल के ब्यौरे दिखाना	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक
2.	8 मासिक विवरणियां प्रस्तुत करना	—वही—

1	2	3
3.	9 (1) 9 (2) चुंगी संग्रह करना	——वही——
4.	12 (ए) (म) व (स) बाकी रकम की अदायगी	——वही——
5.	14 (1) व (2) मिलों के निरीक्षण का अधिकार आदि	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अफसर जिनका ओहदा निरीक्षकों से कम दर्जे का न हो
6.	16 जुर्मों की विवेचना आदि	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलक्टर
7.	18 जुर्मों का मिश्रण	——वही——

[सं० 1/71]

ए० के० बन्धोपाध्याय,

कलक्टर,

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शिलांग ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 17th April 1971

S.O. 1966.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with proviso below sub-rule (2) of rule 4 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby continues the appointment of Shri R. Streenivasan as Chairman, Central Board of Film Censors, Bombay, with effect from April 20, 1971 until further orders.

[No. F.2/101/70-FC.]

K. K. KHAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1966—चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 4 के उप नियम (2) के नीचे परन्तुक के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० स्ट्रीनिवासन की 20 अप्रैल, 1971 से अगले आदेश तक, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को जारी रखती है ।

[संख्या एफ० 2/101/70-एफ० सी०]

के० के० खान,

अवर सचिव ।

New Delhi, the 27th April 1971

S.O. 1967.—In exercise of the power conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the exhibition of the film entitled "The Kremlin Letter"

which has been granted a 'A' Certificate No. 3046, dated 10th March, 1971 by the Central Board of Film Censors, be suspended for a period of two months with effect from the date of this Notification.

[No. F. 9/5/71-FC.]

VIRENDRA D. VYAS, Director.

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1967—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 6 की उप-धारा (2) की क्लाज (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है "दि कैम्लिस लैटर" नामक फिल्म, जिसको केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 'ए' प्रमाण-पत्र संख्या 3046 तारीख 10-3-71 प्रदान किया गया है, का प्रदर्शन इस अधिसूचना की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए रोक दिया जाय।

[संख्या एफ०-9/5/71—एफ० (सी०)]

वीरेन्द्र देव व्यास,
निदेशक।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 29th April 1971

S.O. 1968.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 157 of the Trade and Merchandise Marks Rules, 1959, the Central Government hereby notifies the following alteration made in the Register of Trade Marks Agents in the address of the principal place of business of Shri N. K. Anand, a Registered Trade Mark Agent (Registration No. 50) namely

"N. K. Anand, Advocate, The ACME Company, "Anand Villa" 1, Jaipur Estate, Nizamuddin East, New Delhi-13."

[No. F.29(3)-I.T(TM)/70.]

P. SITARAMAN, Dy. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1971

का० आ० 1968.—व्यापार और वाणिज्य चिह्न नियम, 1959 के नियम 157 के उप-नियम (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन० के० आनन्द, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता (रजिस्ट्रीकरण संख्या 50) के कारबार के मुख्यस्थान के पते में व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में निम्नलिखित परिवर्तन अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

"एन० के० आनन्द, अधिवक्ता,
दी ए सी एम ई कम्पनी,
"आनन्द विला",
1, जयपुर इस्टेट, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-13"।

[सं० 29 (3) आई० टी० (टी० एम०)/70]

प० सीतारामन्, उप सचिव।

(Department of Industrial Development)

(Indian Standards Institution)

New Delhi, 27 April, 1971

S.O. 1969—In pursnance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Insttiution (Certification marks)Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notices that the Standard mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard (s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified:

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification marks), Act, 1952 and the Rules and Regulations framed there under shall come in to force with effect from the dates shown against each.

THE SCHEDULE

Serial No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	IS : 430	Paint remover, solvent type non-flammable.	IS : 430-1964 Specification for paint remover, solvent type, non-flammable (*revised*)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	16 March 1971
	IS :578 . . .	Full-chrome upper leather	ISS : 578-1964 Specification for full-chrome upper leather (*revised*)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' , drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation fo the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicatd in the design.	1 March 1971

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	IS : 691.	Rubber-insulated flexible trailing cables for use in coalmines.	IS : 691-1966 Specification for rubber-insulated flexible trailing cables for use in coalmines.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1 March 1971
	IS : 868	Sealing wax	IS : 868-1956 Specification for sealing wax.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	16 March 1971
	IS : 1084	Manila ropes	IS : 1084-1969 Specification for manila ropes(*second revision*)	The monogram of the Indian Standard Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	16 March 1971
6	IS : 1739	Cotton healds for use in cotton looms.	IS : 1739-1968 Specification for cotton healds for use in cotton looms	The monogram of the Indian Standard Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	16 March, 1971

7	IS :2191 	Wooden flush door shutters with plywood face panels cellular and hollow core type.	IS : 2191 (Part-I)-1966 Specification for wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) (Part I Plywood face panels *(first revision.)*	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	16 February 1971

[No. CMD 13:9]

(औद्योगिक विकास विभाग)

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1971

एस०ओ० 1969. — भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम 1955, के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि मानक-चिह्न जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिये है, भा० मा संस्था निर्धारित किये गये हैं

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 द्वारा और उसके अधीन बन नियमों के निमित्त ये मानक-चिह्न उनके आगे लिखी तिथियों से लागू हो जाएंगे :

अनुसूची

क्रमांक	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की पद-संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS: 430	रंगरोगन अपसारक, घोल-कनुमा, अज्वलनशील	IS:430—1964 रंग रोगन अपसारक घोलक नुमा, अज्वलनशील, की विशिष्टि (पुनरीक्षित।)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी हुई है।	16 मार्च 1971

2.	IS:578	उपल्ले का फुलक्रोम चमड़ा	IS:578–1964 उपल्ले के फुलक्रोम चमड़े की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी हुई है :	1 मार्च 1971
3.	IS:691	कोयले की खानों में उपयोग के लिए रबड़ रोधित नम्य ट्रेलिंग केबल	IS:691–1966 कोयले की खानों में उपयोग के लिए रबड़-रोधित नम्यो ट्रेलिंग केबलों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी हुई है :	1 मार्च 1971
1.	IS: 868	सील लगाने वाली मोम	IS : 868–1956 सील लगाने वाली मोम की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी हुई है :	16 मार्च 1971

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.	IS:1084	सन के रस्से	IS:1084–1969 सन के रस्सों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी हुई है :	16 मार्च 1971
6.	IS:1739	सूती करघों में उपयोग के लिए सूती होल्ड	IS: 1739–1968 सूती करघों में उपयोग के लिए सूती होल्डों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी हुई है :	16 मार्च 1971
7.	IS :2191	कोषीय और खोखले मध्य भाग वाले ऊपर प्लाइवूड के तख्ते लगे लकड़ी के समतल किवाड :	IS: 2191–भाग (I) 1966 लकड़ी के समतल दरवाजों के किवाड़ों (कोषीय और खोखले मध्य भाग वाले) की विशिष्टि, भाग I ऊपर प्लाइवुड के तख्ते लगे हुए (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है, और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी हुई है ।	16 फरवरी 1971

[सं० सी० एम० डी०/13:9]

S.O. 1970— In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Stanadrd (Marks), design(s), of which together with the verbal description of the design(s)and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1 December 1970:

THE SCHEDULE

Serial No.	Design of the Standard Mark	Product Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS : 86	Oil paste for paints to Indian Standard colours.	IS : 86-1950 Specification for oil paste for paints to Indian Standard colours.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.
2	IS 94	Oil paste for paints to Indian Standard colours.	IS : 94-1950 Specification for oil paste for paints to Indian Standard colours.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD 13 : 9]

A. K. GUPTA,
Deputy Director General.

एस० ओ० 1970--भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम 1955 के नियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि मानक चिह्न जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के शीर्ष सहित नीचे अनुसूची में दिए हैं, भा मा संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निबन्धन ये मानक चिह्न 1 दिसम्बर 1970 से लागू हो जाएंगे :

अनुसूची

क्रमांक	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS: 86	भारतीय मानक रंगों के अनुरूप रंग-रोगनों के लिए तेल पेस्ट	IS: 86–1950 भारतीय मानक रंगों के अनुरूप रंग-रोगनों के लिए पेस्ट की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है, और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी हुई है :
2.	IS: 94	भारतीय मानक रंगों के अनुरूप रंग-रोगनों के लिए तेल पेस्ट	IS: 94–1950 भारतीय मानक रंगों के अनुरूप रंग-रोगनों के लिए तेल पेस्ट की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है, और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी हुई है :

[सं० सी० एम० डी०/13: 9]

ए० के० गुप्ता,
उप महानिदेशक ।

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th April 1971

S.O. 1971.—/RLIUR/18/2.—In pursuance of rule 18 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 and in partial modification of the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. 2582/RLIUR/18/1 dated the 24th July, 1970, the Central Advisory Council of Industries hereby appoints Shri S. S. Kanodia and Shri B Mitter to be members of the Reviewing Sub-Committee of the Council till the 4th March, 1972, in place of Shri D. C. Kothari and Shri Keshub Mahindra respectively.

[No. 11(1)/Lic.Pol./70.]

R. C. SETHI, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1971/आर० एल० आई० यू० आर०/18/2—औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन और लाइसेंसीकरण सम्बन्धी नियम, 1952 की धारा 18 तथा भारत सरकार, औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), के दिनांक 24 जुलाई, 1970 के आदेश, संख्या 2582/आर० एल० आई० यू० आर०/18/1 में किये गये आंशिक संशोधन के अनुसरण में, केन्द्रीय औद्योगिक सलाहकार परिषद्, सर्वश्री डी० सी० कोठारी और केशव मोहिन्द्रा के स्थान पर क्रमशः सर्वश्री एस० एस० कनोडिया और बी० मित्रा को 4 मार्च, 1972 तक के लिए परिषद् की संवीक्षा उप-समिति का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं० 11(1)—लाइ० पालि०/70]

आर० सी० सेठी, अवर सचिव।

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th April 1971

S.O. 1972.—/IDRA/6/70.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 5(1) and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints till 9th September, 1972 Shri S. N. Shivapuri of M/s. Ancillary Automobiles Industries (P) Ltd., Calcutta to be a member of the Development Council established by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade No. S.O. 3243-IDRA/6/16, dated the 10th September, 1970 for the scheduled industries engaged in the manufacture of production of Automobiles, Automobile of Ancillary Industries Transport Vehicle Industries, Tractors, Earth Moving Equipment and Internal Combustion Engines and directs that the following amendments shall be made in the said Order, namely:

In the said Order:

For the name of "Shri K. L. Nanjappa" in entry No. 28, the name of "Shri S. N. Shivapuri, M/s. Ancillary Automobile Industries (P) Ltd., Calcutta" shall be substituted.

[No. 1(33)/70-A.E. Ind. (I).]

S. R. KAPUR, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1972.—**आई डी आर ए/6/70** :—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65वां) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विकास परिषदें (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 5(1) और 8 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैं० एन्सिलरी आटोमोबाइल्स इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता के श्री एस०एन० शिवपुरी को 8 सितम्बर, 1972 तक के लिए भारत सरकार के औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3243–आई डी आर ए/6/16 दिनांक 10 सितम्बर, 1970 के द्वारा स्थापित मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ी के सहायक उद्योगों, परिवहन गाड़ी उद्योगों, ट्रक्टरों, मिटटी खोने के उपकरण तथा इंटरनल कम्बशन इंजनों के निर्माण अथवा उत्पादन में रत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद का सदस्य नियुक्त करती है और निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा; अर्थात् :—

उक्त आदेश में:

प्रविष्टि संख्या 28 में "श्री के० एल० नांजपा" के नाम के स्थान पर "श्री एस० एन० शिवपुरी, मैं० एन्सिलरी आटोमोबाइल इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड कलकत्ता" का नाम रखा जाएगा।

[संख्या 1(33)/70–ए०ई०एण्ड (1)]

एस०आर० कपूर, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

CARDAMOM CONTROL

New Delhi, the 3rd May 1971

S.O. 1973.—In pursuance of clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), read with rules 3 and 5 of the Cardamom Rules, 1966, the Central Government hereby appoints Shri Jayantilal Manekchand Gandhi as a member of the Cardamom Board, Vice Shri Abhechand D. Gandhi, died and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade and Supply No. S.O. 1433, dated the 15th April, **1969, namely:—**

In the Table under the said notification, for the entry in the first column against serial No. (14), the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri Jayantilal Manekchand Gandhi, Messrs. Gandhi Sons, 232, Samuel Street, Bombay-3".

[No. F.29(88)Plant(B)/68.]

A. K. MISRA, Dy. Director.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

इलायची नियन्त्रण

नई दिल्ली, 3 मई 1971

का० आ० 1973—इलायची नियमावली, 1966 के नियम 3 तथा 5 के साथ पठित, इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में

केन्द्रीय सरकार, श्री अभयचन्द डी० गांधी की मृत्यु के कारण, उनके स्थान पर श्री जयन्ति लाल मानक चन्द गांधी को इलायची बोर्ड के एक सदस्य के रूप में, एतद्द्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1433 दिनांक 15 अप्रैल, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत सारणी में, क्रमांक (14) के सामने पहले स्तम्भ में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"श्री जयन्ति लाल मानक चन्द गांधी,
मसर्स, गांधी सन्स,
232, सैमुअल स्ट्रीट, बम्बई-3"

[सं० फा० 29(88)—प्लांट (बी०)/68]

ए० के० मिश्रा,
उप-निदेशक ।

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

(Central Licensing Area)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 13th January 1971

S.O.1974.—M/s. Saturn Private Ltd. Industrial Area, E-55. Jullundur City were granted licence No. P/S/1614540/C/XX/32/D/29-30, dated 11th August, 1969 for Rs. 4166 for Import of Tapper Roller Bearings other than those specified in Appendix 14(6) of AM.70 Red Book (Vol. I). They have applied for duplicate copy of Custom purpose copy and Exchange Control Copy of the licence on the ground that the Original Licence *i.e.* Customs and Exchange Control Copies thereof have been lost/misplaced. It is further stated by the party that original licence in duplicate was not registered with any customs authority and was not utilised at all.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that the original Custom Purpose copy of Licence No. P/S/1614540/C, dated 11th August, 1969 in duplicate has been lost/misplaced and direct that the duplicate licence (Custom/Exchange Control copy) may be issued to the applicant. The original Cutom/Exchange Control copy of licence in question is hereby cancelled.

[No. P/S-8/N/AM.70/AU PB/CLA.]

A. L. BHALLA,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports,
For Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

संयुक्त मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी 1971

एस०ओ० 1974.—सर्वश्री सैटर्न प्रा० लि०, इन्डस्ट्रियल एरिया, ई-55, जालंधर नगर को रैड बुक (वलम 1) अप्रैल-मार्च 1970 के परिशिष्ट 14(6) में विशिष्टिकृत से भिन्न टपर रोलर

बियरिंग्स के आयात के लिए 4166 रुपये मात्र के लिए एक लाइसेंस सं० पी०/एस०/1614540/सी० एक्स एक्स/32/डी०/29-30 दिनांक 11-8-1969 जारी किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की सीमा-शल्क विभाग संबंधी प्रति तथा मुद्रा विनिमय प्रति की अनुलिपि के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस अर्थात् उसकी सीमाशुल्क विभाग संबंधी प्रति तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है। पार्टी द्वारा आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस दोनों प्रतियों में किसी सीमाशल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया था।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है।

मैं सन्तुष्ट हूं कि दो प्रतियों में लाइसेंस सं० पी०/एस०/1614540/सी०, दिनांक 11-8-69 की मूल सीमाशल्क विभाग संबंधी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि (सीमा-शल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) जारी की जाए। विषयाधीन लाइसेंस की मूल सीमा-शल्क/मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[सं० पी०/एस०-8/एन०/ए० एम०-70/ए० यू० पी० बी०/सी० एल० ए०]

ए० एल० भल्ला,
उप-मख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 4th March, 1971

S.O. 1975—M/s. The Bombay Samachar Pvt. Ltd., Bombay were granted an import licence No. P/A/1326790/T/UR/35/U/31/32, dated 1st June, 1970 for Rs. 276000/- (Rupees Two lakh and seventy-six thousand only) They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes/Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes/Exchange Control Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes/Exchange Control copy was registered with the Customs authorities at Bombay. Bank Ltd., unutilised and utilised full/partly. It was utilised for Rs. 66145/- and the balance available on it was Rs. 209855/- (Two lakh nine thousand eight hundred and fifty-five only).

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit alongwith a certificate from Notary Public Bombay (Maharashtra State). I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes/Exchange Control Purposes copy of the licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9 (cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended the said original Customs Purposes/Exchange Control Purposes copy of licence No. P/A1326793/TCK/35/H/31-32, dated 1st June, 1970 issued to M/s. The Bombay Samachar Pvt. Ltd., Bombay, is hereby cancelled

3. A duplicate Customs Purposes/Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licence.

[No. 44.V/BP-67/70-71/NPCIB.]

SUSHIL SINGH,
Dy. Chief Controller.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च 1971

एस०ओ० 1975.—सर्वश्री दी बम्बई समाचार प्रा० लि०, बम्बई को 2,76,000 रुपये (दो लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी०/ए०/1326793/टी०/यू०

आर०/35/एच०/31-32 दिनांक 1-6-70 जारी किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई है अथवा नष्ट हो गई है। आगे यह सूचना दी गई है कि मूल सीमाशुल्क प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी बम्बई से पंजीकृत कराई थी। इसका उपयोग 66145 रुपये के लिए हो गया था और इस पर उपलब्ध 209855 रुपये (दो लाख नौ हजार आठ सौ पचपन रुपये मात्र) शेष थे।

2. अपने तर्क की पुष्टि में आवेदक ने नोटरी पब्लिक बम्बई, (महाराष्ट्र राज्य) से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई है। इसलिए, यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सी०सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री दी बम्बई समाचार प्रा० लि०, बम्बई को जारी किये गए लाइसेंस सं० पी०/ए०/1326793 टी०/यू० आर०/35/एच०/31-32, दिनांक 1-6-70 की मूल सीमाशुल्क प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या 44-5/बी० पी०-67/70-71/एन० पी० सी० आई० बी०]

सरदूल सिंह,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

(Central Licensing Area)

ORDERS

New Delhi, the 19th March 1971

S.O. 1976.—M/s. M. S. Brothers and Co., 929/21, Mahmood Building, Geejgarh Road, Topkhana Hazoori, Jaipur-3 were granted licence No. P/1/1316037/C dated 22nd October, 1970. They have informed that the Original Copies of the said import licence have been lost.

I am satisfied that the Original Exchange and Custom purpose copies of Licence No. P/L/1316037/C, dated 22nd October, 1970 have been lost. The Original Exchange and Custom purpose copies of licence are cancelled.

[No. Gem. 117/AJ.70/SC.IV/CLA.]

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1971

एस० ओ० 1976.—सर्वश्री एम० एस० ब्रादर्स एण्ड कम्पनी, 929/21, महमूद बिल्डिंग गेजगढ़ रोड, तोपखाना हजूरी, जयपुर-3 को लाइसेंस संख्या पी/एल/1316037/सी, दिनांक 22-10-70 प्रदान किया गया था। उन्होंने सूचना दी है कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल प्रतियां खो गई हैं।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या पी/एल/1316037/सी, दिनांक 22-10-70 की मूल मुद्रा विनिमय तथा सीमा-शुल्क प्रतियां खो गई हैं। लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय और सीमा शुल्क प्रतियां रद्द की जाती हैं।

[संख्या : जैम 117/एज-70/एस सी. 4/सी एल ए]

S.O. 1977.—M/s. K. L. Bhatia, 2217, Chuna Mandi, Paharganj, New Delhi were granted import licences No. P/K/1339295/C dated 11th February, 1971. They have applied for duplicate copies (Exchange purposes and Customs copies) of licence on the ground that the original copies of the said import licence have been lost. It is further stated that the Original licences were not utilized at all and that the duplicate copies are required to cover the full amount.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Exchange and Custom Purpose copies of licence No. P/K/1339295/C, dated 11th February, 1971 have been lost and direct that the duplicate licence should be issued to the applicant. The Original Exchange and Customs purpose copies of licence are cancelled.

[No. Gem. 191/AJ. 70/SC. IV/CLA.]

D. S. MORKRIMA, Dy. Chief Controller.

एस०ओ० 1977.—सर्वश्री के०एल० भाटिया, 2217, चूना मण्डी पहाड़गंज, नई दिल्ली को एक आयात लाइसेंस संख्या पी/के/1339295/सी, दिनांक 11-2-71 प्रदान किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियों (मुद्रा विनिमय तथा सीमा-शुल्क प्रतियों) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल प्रतियां खो गई हैं। आगे यह उल्लेख किया गया है कि मूल लाइसेंसों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया था और अनुलिपि प्रतियों की आवश्यकता पूर्ण मूल्य के लिए है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि लाइससां संख्या पी/के/1339295/सी, दिनांक 11-2-71 की मूल मुद्रा विनिमय और सीमा-शुल्क प्रतिय खो गई हैं और निदेश देता हूं कि आवेदन को लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए। लाइसें की मूल मुद्रा विनिमय तथा सीमा शुल्क प्रतियां रद्द की जाती हैं।

[सं० जैम 191/एज०/70/एस०सी० 4/सी०एल०ए०]

डी० एस० मोरक्रीमा,
उपमुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 27th April 1971

S.O. 1978.— The Chief Purchase Officer, Beas Purchase Organisation Talwara Township was granted licence No. G/A/1037221 dated 30th January, 1969 for import of spares for 21 tons battery trolley locomotives type valued at Rs. 3,48,499. He has requested for the issue of duplicate Custom purposes copy of licence on the ground that the original custom copy of the licence has been lost by him. It has been further reported by the licensee that this licence was lost after utilisation of amount to the extent of Rs. 39,000 and this licence was registered with the Collector of Customs, Bombay.

In support of their contention the applicant have filed affidavit. The undersigned is satisfied that the original custom copy of the licence No. G/A/1037221 dated 30th January, 1969 has been lost and directs that duplicate copy of the said licence should be issued to him. The original custom copy has been cancelled. Duplicate copy of the licence is being issued separately.

[No. 3/SG/79/68. 69/PLS/B/122.]

S. K. USMANI,
Dy. Chief Controller of Imports and Exports.
For Chief Controller of Imports and Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 1971

एस०ओ० 1978.—दि चीफ परचेज आफिसर, ब्यास परचेज आर्गेनाइजेशन तलवाड़ा टाउनशिप को लोकोमोटिव किस्म की—21 टन बैट्टीट्रालि के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए 3,48,499/—रुपये का आयात लाइसेंस संख्या जी/ए० 1037221, दिनांक 30—1—69 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनके द्वारा मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह बताया गया है कि उक्त लाइसेंस सीमा-शुल्क समाहर्ता बम्बई के पास पंजीकृत कराने तथा 39,000/—रुपये तक का उपयोग करने के पश्चात खो गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र जमा किया है। अधोहस्ताक्षरी इससे संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या जी/ए/ 1037221, दिनांक 30—1—69 की मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति रद्द की जाती है। लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या 3/एस० जी०/79/68—69
पी० एल० एस०/बी० 122]

एस०के० उस्मानी,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात—निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 28th April 1971

S.O. 1979.—Mr. Gangalal Caseva, State Trading Corporation of India Ltd. New Delhi was granted Custom Clearance Permit No. P/J/2374499/N/MP/37/H/31-32 dated 21st December, 1970 for Rs. 20,000 only for import of a 1970 Fiat 125-S. Car has applied for a duplicate copy of the Custom clearance permit as the original Customs Clearance Permit has been lost. It is further stated that the original Custom Clearance Permit was not registered with any Custom House and not utilised.

In support of this contention Mr. Gangalal Caseva has filed an affidavit. He has undertaken to return the Custom Clearance Permit if traced later to this office for record. I am satisfied that the original Custom Clearance Permit No. P/J/2374499N/MP/37/H/31-32 dt. 21st December, 1970 has been lost and direct that a duplicate Custom Clearance permit should be issued to him. The original Custom Clearance Permit may be treated as cancelled.

[No. 2(B-224)/70-71/BLS/299/371.]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller,
of Imports & Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली 29 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1979—श्री गंगालाल कसेवा, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली को एक 1970 फिएट 125-एस कार के आयात के लिए 20000/—रुपये मात्र के लिए एक सीमा शुल्क निकासी परमिट संख्या पी०/जे० / 2374499 / एन/ एमपी /37 / एच/ 31-32, दिनांक 21-12-70 प्रदान किया गया था। उन्होंने सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है। आगे यह उल्लेख किया गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी सीमा शुल्क कार्यालय से पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका उपयोग नहीं हुआ था।

अपने इस तर्क के समर्थन में श्री गंगालाल कसेवा ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। उन्होंने यह वचन दिया है कि यदि सीमा शुल्क निकासी परमिट बाद में मिल गया तो उसको रिकार्ड के लिए इस कार्यालय को वापिस कर देंगे। मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट संख्या पी / जे 2374499 / एन / एम पी 37 / एच /31-32, दिनांक 21-12-70 खो गया है और निदेश देता हूं कि आवेदक को सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा शुल्क परमिट को रद्द समझा जाए।

[संख्या 2 (बी०224)/ 70-71 / बी०एल०एस०]

के० एन० कपूर,

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971